सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो इसे एक लक्ष्य से बांधें न कि लोगों या चीजों से !

वर्ष 01, अंक 182, नई दिल्ली

गुरुवार, 14 सितम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

सरकारी पोर्टल पुराने वाहनों को वापस पाने में मालिकों की मदद करेगा : परिवहन मंत्री

संजय बाटला

नई दिल्ली। परिवहन विभाग उन लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा जो अपने पुराने वाहनों को चलने के कारण जब्त कर लिए जाने या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए जाने के बाद उन्हें छुड़ाना चाहते हैं।

मार्च में अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए विभाग द्वारा एक व्यापक अभियान शुरू किया गया था - पेट्रोल वाहनों के मामले में 15 वर्ष और डीजल वाहनों के मामले में 10 वर्ष। अब तक लगभग 15,000 दोपहिया और चार पहिया वाहनों को जब्त किया गया है।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, 'हम जब्त किए गए वाहन को वापस पाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि यह लोगों के लिए सुविधाजनक हो, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल भ्रष्टाचार की गुंजाइश को खत्म कर देता है।ह उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के मुताबिक जब्त किए गए वाहनों को वापस लाने के लिए जल्द ही एक नीति बनाई जाएगी। नीति के तहत, अदालत के निर्देश के अनुसार, मालिकों को अपने वाहनों को छुड़ाने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा। परिवहन विभाग ने पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया था जिसके तहत लोग जब्त वाहनों को छुड़वा सकें। गहलोत ने इस पर आपत्ति जताई थी और विभाग को यह कहते हुए अभियान रोकने के लिए लिखा था कि यह अभ्यास 'आक्रामक' था और 'इसके पास सरकार की मंजूरी नहीं थी'। मामला अदालत में गया जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्क्रैपिंग के लिए अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए 'जीवन के अंत' वाहनों को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ शर्तों के तहत। मालिक स्थायी रूप से रखने का वादा करेंगे। वाहनों को निजी स्थान पर रखें या उन्हें बाहर स्थानांतरित करें।

मालिक वाहनों को स्थायी रूप से निजी स्थान में रखने या उन्हें दिल्ली-एनसीआर से बाहर स्थानांतरित करने का वादा करेंगे, न कि ग्रामीण इलाकों में। शहर की सीमा के भीतर.

अभियान शुरू करते समय, विभाग ने कहा था कि इसका उद्देश्य शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों को अपने पुराने वाहनों को सड़क पर छोड़ने के बजाय स्क्रैप करने के लिए प्रेरित करना था। मालिकों को केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा तय दरों के मुताबिक मुआवजा दिया गया। हालांकि, मई में, गहलोत ने विभाग को पार्क किए गए वाहनों को हटाने से रोकने का निर्देश दिया, जिसके बाद अभियान रोक दिया गया। लेकिन 29 मई को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में चलने वाले या पार्क किए गए सभी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखे जाने के बाद विभाग ने अभियान फिर से शुरू कर दिया।

आयुक्त को जारी एक आदेश में, मंत्री ने कहा था: "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभाग सड़क पर पार्क किए गए वाहनों को जब्त करने और उसके बाद स्क्रैपिंग के लिए भेजने का अपना अभियान जारी रखता है।"

दिल्ली ने 55 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है, उनमें से कई बहुत अधिक उम्र के हैं लेकिन फिर भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं।

भारतीय वायुसेना के बेड़े में बढ़ेगा यह खास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट

परिवहन विशेष न्यूज

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सेविले में एयरबस द्वारा निर्मित पहला सी-295 परिवहन विमान हासिल करेंगे। भारतीय वायुसेना ने 56 ऐसे विमानों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना लगातार अपने बेड़े को बढ़ाती जा रही है। साथ ही वो इस बात पर भी जोर दे रही है कि उसके बेड़े में शामिल होने वाले किसी भी तरह के विमान देश में ही बनाए गए हों। इसी क्रम में, अब देश की वायुसेना के पास जल्द सी-295 परिवहन विमान (ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट) मौजूद होगा।

विमान के लिए वडोदरा क्यों खास

दरअसल, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सेविले में एयरबस द्वारा निर्मित पहला सी-295 परिवहन विमान हासिल करेंगे। बता दें, भारतीय वायुसेना ने 56 ऐसे विमानों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 16 विमान स्पेन में बनेंगे। वहीं अन्य 40 को गुजरात के वडोदरा में एयरबस-टाटा का संयुक्त उद्यम बनाएगा।

इस माह के अंत में बेड़े में शामिल होने की उम्मीद

इससे पहले रक्षा अधिकारी ने बताया था कि वायुसेना प्रमुख बुधवार को सेविले स्थित एयरबस संयंत्र में पहला विमान हासिल करेंगे। वहां एक समारोह के बाद विमान भारत के लिए उड़ान भरेगा। सितंबर के अंतिम सप्ताह में हिंडन वायुसेना केंद्र में एक समारोह में इस विमान को सेवा में शामिल किए जाने की उम्मीद है।

साल 2001 में हुआ था अनुबंध

रक्षा मंत्रालय और स्पेन की एयरबस रक्षा एवं अंतरिक्ष कंपनी ने सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए 56 सी-295 विमान निर्माण संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय उप वायुसेना प्रमुख रहे एअर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने अनुबंध समझौते की अगुआई की थी।

ओवरटेक करते समय स्कूटी सवार दंपती ट्रॉला के नीचे आया, दोनों की गई जान

राजनगर एक्सटेंशन में बुधवार को एक ट्रॉला को ओवरटेक कर स्कूटी मोड़ने के दौरान हादसा हो गया जिसमें स्कूटी सवार दंपती की मौत हो गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने ट्रॉला को कब्जे में ले लिया है। स्कूटी सवार दंपती की पहचान अरुण और उनकी पत्नी सुनीता के रूप में हुई है जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले थे।

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन में बुधवार दोपहर को एक ट्रॉला को ओवरटेक कर उसके सामने से जल्दबाजी में स्कूटी मोड़ने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें स्कूटी सवार दंपती की ट्रॉला की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। नंदग्राम पुलिस ने ट्रॉला को कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद लोगों का कहना है कि स्कूटी सवारों ने ट्रॉला को ओवरटेक करने में जल्दबाजी और गलती की है। यदि वे ट्रॉला के निकलने का इंतजार कुछ सेकेंड कर लेते, इसके बाद कट पर स्कूटी मोड़ते तो हादसे की चपेट में आने से बच सकते थे।

क्या एक अक्तूबर से कारों में लगेंगे छह एयरबैग? नितिन गडकरी बोले- अभी अनिवार्य नहीं करेंगे

परिवहन विशेष न्यूज

वाहनों में सुरक्षा को लेकर पिछले काफी समय में एयरबैग की संख्या बढ़ाकर छह करने को लेकर लंबे समय से चर्चा की जा रही थी। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से जानकारी दी गई है कि सरकार की ओर से कारों में छह एयरबैग को अनिवार्य नहीं किया जाएगा।

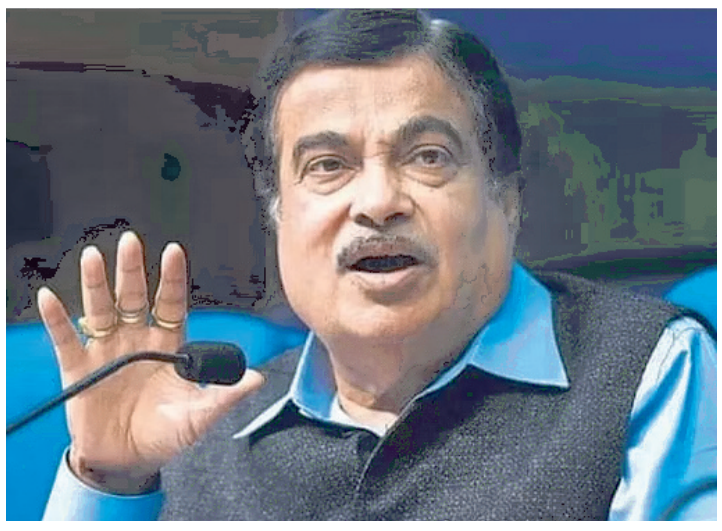

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दिल्ली में आयोजित एसीएम के कार्यक्रम में एयरबैग्स पर जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल की शुरुआत में नए क्रैश टेस्ट नियम लागू होने के बाद से अब केंद्र सरकार कारों में सुरक्षा के लिए छह एयरबैग के सुरक्षा नियम को अनिवार्य नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि देश में कई वाहन निर्माताओं की ओर से पहले से ही अपनी कारों में छह एयरबैग दिए जा रहे हैं। कंपनियों की ओर से ऐसी कारों के विज्ञापन भी किए जा रहे हैं। जिसके बाद छह एयरबैग को अनिवार्य किए जाने की जरुरत नहीं है। अब ग्राहक सुरक्षा को लेकर जागरूक हो गए हैं। जिसके बाद ऐसी कारों की मांग में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें छह एयरबैग की सुरक्षा मिलती है।

पहले किया था यह फैसला

केंद्र सरकार की ओर से साल 2022 में कारों में छह एयरबैग पर फैसला लिया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से ही पिछले साल इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई थी। तब केंद्रीय मंत्री की ओर से जानकारी दी गई थी कि ऑटो उद्योग के सामने आ रही वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं और व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, 01 अक्टूबर 2023 से यात्री कारों (एम -1 श्रेणी) में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

जताई थी चिंता

साल 2022 में ही केंद्रीय मंत्री की ओर से एक चैनल को इंटरव्यू दिया गया था। जिसमें उन्होंने चार पहिया वाहनों में सुरक्षा पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कंपनियां निर्यात होने वाली कारों में तो छह एयरबैग देती हैं, लेकिन जब वही यूनिट भारत के लिए बनाई जाती है तो उसमें केवल चार एयरबैग ही दिये जाते हैं। एक एयरबैग को बनाने की कीमत महज नौ सौ रुपए आती है। अगर बड़ी संख्या में प्रोडक्शन हो तो एयरबैग की कीमत भी काफी कम हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- क्या ड्राइविंग लाइसेंस के मुद्दे पर कानून में बदलाव की जरूरत है

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या कानून में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या कोई व्यक्ति जो हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, वह किसी विशेष वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल (परिवहन वाहन) को कानूनी रूप से चलाने का हकदार है।

नईदिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या कानून में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या कोई व्यक्ति जो हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, वह किसी विशेष वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल (परिवहन वाहन) को कानूनी रूप से चलाने का हकदार है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि ये नीतिगत मुद्दे हैं जो लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। पीठ ने कहा कि सरकार को इस मामले पर ₹नया सिरे से विचार₹ करने की जरूरत है और कहा कि इसे नीतिगत स्तर पर उठाया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से दो महीने के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने और किए गए निर्णय के बारे में उसे अवगत कराने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के किसी भी व्याख्या को सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन के अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के वैध चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने पहले ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से इस कानूनी सवाल पर सहायता मांगी थी कि क्या एक व्यक्ति जो एक हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, क्या वह किसी विशेष वजन के परिवहन वाहन को कानूनी रूप से चलाने का हकदार है। संविधान पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थिति जानना आवश्यक होगा, क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में, शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को केंद्र ने स्वीकार कर लिया है और नियमों को इस निर्णय के अनुरूप संशोधित किया गया है। मुकुंद देवांगन मामले में, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि परिवहन वाहन, जिनका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है, को एलएमवी की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है।

कानपुर को 150 नई बसें आवंटित: जनवरी तक मिलेंगी ई-बसें, न्यू कानपुर सिटी में बनेगा चार्जिंग डिपो

ई-बस प्रबंधन मेन रूट के बजाय बसों को कनेक्टिंग रूट पर भी चलाएगा। इससे तेजी से बढ़ रही आबादी की परिवहन जरूरत को पूरा करने के लिए धड़ल्ले से निकल रहे ई-रिक्शों के बेतरतीब संचालन और हर रूट पर लगने वाले जाम से निजात भी मिलेगी।

कानपुर। शहर में प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत कानपुर शहर को आवंटित 150 नई इलेक्ट्रिक बसें जनवरी तक ई-बसों के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। केसीटीएसएल (कानपुर नगरीय परिवहन सेवा) ने नई बसों की चार्जिंग के लिए नया डिपो बिठूर-मंधना के बीच में न्यू कानपुर सिटी में बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए साढ़े तीन एकड़ जमीन की जरूरत है। जिला प्रशासन के माध्यम से ग्राम समाज की जमीन को हासिल कर डिपो बनाने का काम शुरू करा दिया जाएगा।

हर तीन मिनट में मिलेंगी बसें, कनेक्टिंग रूट पर चलेंगी

नई बसों के मिलने से शहर में केसीटीएसएल के बेड़े में 250 ई-बसें हो जाएंगी। अभी चल रहीं 100 बसें शहर में अहिरवां के संजीवनगर से आईआईटी, बिठूर, जाजमऊ के अलावा घाटमपुर, रनियां, उन्नाव और बिंदकी पर चल रही हैं। यह मुख्य रूट हैं। अभी यात्रियों को औसत 10 मिनट में दूसरी बस मिलती है। 150 नई बसों के मिलने से हर तीन मिनट में बसें मिलेंगी।

जाम से निजात भी मिलेगी

इससे यात्री ई-रिक्शा, ऑटो, टेंपो में बैठने के बजाय एसी ई-बस का तीन मिनट तक इंतजार कर लेगा। ई-बस प्रबंधन मेन रूट के बजाय बसों को कनेक्टिंग रूट पर भी चलाएगा। इससे तेजी से बढ़ रही आबादी की परिवहन जरूरत को पूरा करने के लिए धड़ल्ले से निकल रहे ई-रिक्शों के बेतरतीब संचालन और हर रूट पर लगने वाले जाम से निजात भी मिलेगी।

अहिरवां में चार्जिंग डिपो का होगा विस्तार

अभी अहिरवां के संजीवनगर में केसीटीएसएल के चार्जिंग डिपो में 100 बसों के चार्ज होने की व्यवस्था है। यहां पर खाली पड़ी जगह पर 50 बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन का विस्तार हो रहा है। इससे आने वाली नई 150 बसों में 50 संजीवनगर में चार्ज होंगी। बाकी 100 बसों को न्यू कानपुर सिटी में प्रस्तावित चार्जिंग डिपो में चार्ज होंगी।

कानपुर को प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत 150 बसों का आवंटन हुआ है। जनवरी तक बसों की खेप आनी शुरू हो जाएगी। बसों की चार्जिंग के लिए न्यू कानपुर सिटी में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जमीन का सर्वे हो रहा है।

-लव कुमार सिंह, एमडी, केसीटीएसएल

दिल्ली परिवहन विभाग ने BS 6 डीजल बसों और टेम्पो ट्रेवलर का रजिस्ट्रेशन खोल दिया है

वास्तव में ये रजिस्ट्रेशन पिछले महीने 25 जुलाई को खोल देना चाहिए था : दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग ने BS 6 डीजल बसों और टेम्पो ट्रेवलर का रजिस्ट्रेशन खोल दिया है, वास्तव में ये रजिस्ट्रेशन पिछले महीने 25 जुलाई को खोल देना चाहिए था. लेकिन दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलास गेहलोत ने इस फ़ाइल को एक महीने से ऊपर पेंडिंग रखा. और दिल्ली का ट्रांसपोर्टर्स परेशान होता रहा बल्कि काफी ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल बसों और टेम्पो ट्रेवलर का रजिस्ट्रेशन दुसरे राज्यों से करवाया. इस से दिल्ली सरकार को भी लाखों रुपए राजस्व का नुक्सान हुआ.

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने लगातार दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री आशीष कुंद्रा जी, और स्पेशल कमिश्नर श्री सहजहाद आलम और शिल्पा शिंदे जी, सब से मिलकर उनको डीजल BS 6 बसों और टेम्पो ट्रेवलर के रजिस्ट्रेशन खोलने के लिए ज्ञापन भी दिए.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, संजय सम्राट का कहना है की जब 24 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी श्री कैलास गेहलोत जी, परिवहन मंत्री ने डीजल बसों की फ़ाइल को जानभूझ कर पेंडिंग रखा तब मजबूर होकर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने 29 अगस्त को भारी धरना प्रदर्शन श्री अरविन्द केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली, के निवास पर किया बल्कि दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलास गेहलोत के इस्तीफे की मांग भी की. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के उप राजयपाल श्री विनय सक्सेना को भी श्री कैलाश गेहलोत की शिकायत भी की और उन्हें अपनी मांगो का ज्ञापन भी सौंपा.

संजय सम्राट का कहना है की G 20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गेहलोत जी को BS 6 डीजल बसों का रजिस्ट्रेशन एक महीने पेहले खोलना चाहिए था.

काफी ट्रांसपोर्टर्स इस वजह से नई बसें नहीं खरीद पाए और दिल्ली में G 20 शिखर सम्मेलन में बसों की कमी रही, इसलिए काफी बसें और टेम्पो ट्रेवलर दुसरे राज्यों से किराये पर मंगाने पड़े.

संजय सम्राट का कहना है की 29 अगस्त के प्रदर्शन से, जब बात मीडिया में आई तब जाकर श्री कैलाश गेहलोत जी ने

डीजल BS 6 के रजिस्ट्रेशन खोलने की कोशिश करी, और 29 अगस्त से भी आज 13 सितंबर 2023 को रजिस्ट्रेशन खुले है.

संजय सम्राट का कहना अभी दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री श्री कैलास गेहलोत के और धरने प्रदर्शन होंगे क्योंकि अभी भी पेनिक बटन की अनिवार्यता को इन्होने खत्म नहीं किया है आज तक दिल्ली सरकार ने कोई कॉल सेंटर नहीं बनाया है जबकि अभी भी हमारे टैक्सी बस मालिकों से 9000 रुपए से लेकर 22000 रुपए से ज्यादा पेनिक बटन के नाम पर लिए जा रहे है.

ऐसा ही स्पीड लिमिट डिवाइस (स्पीड गवर्नर) अभी तक आल इंडिया टूरिस्ट परमिट टैक्सी बसों से नहीं हटाया गया है. जिसकी वजह से बड़े हादसे हो सकते है, खासकर महिलाओ की सुरक्षा का मामला भी इससे जुडा है, हाईवे या एक्सप्रेस वे पर गुंडे बदमाश टैक्सी बसों को ओवरटेक करके लूट पाट कर सकते है. इसके अलावा चार धाम यात्रा पर पहाड़ो में टैक्सी बसों को चढ़ने में दिक्कत आती है और गाड़ियों की दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ो में सीधी चढ़ाई होती है और स्पीड लिमिट डिवाइस से गाड़ियाँ पिक उप नहीं कर पाती.

संजय सम्राट का कहना है की दिल्ली में डीजल BS 6बसों और टेम्पो ट्रेवलर के रजिस्ट्रेशन खुलने से पर्यावरण भी सही रहेगा क्योंकि ये बसें CNG गाड़ियों से भी कम धुआँ देती है.

दिल्ली की जनता को भी बसों के रजिस्ट्रेशन से फायदा होगा क्योंकि अरबो रुपए दिल्ली सरकार को राजस्व के रूप में मिलेंगे.

दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स में काफी ख़ुशी का माहौल है. क्योंकि इस से पेहले दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स को दुसरे राज्यों की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में धक्के खाने पड़ते थे और वहाँ पर कोई भी काम बगैर दलाल के नहीं होते थे और काफी रुपया दलालो को देना पड़ता था. काफी ट्रांसपोर्टर्स ने दिल्ली छोड़कर दुसरे राज्यों में अपने ऑफिस भी खोल लिए थे और घर भी शिफ्ट कर लिए था.

dnl

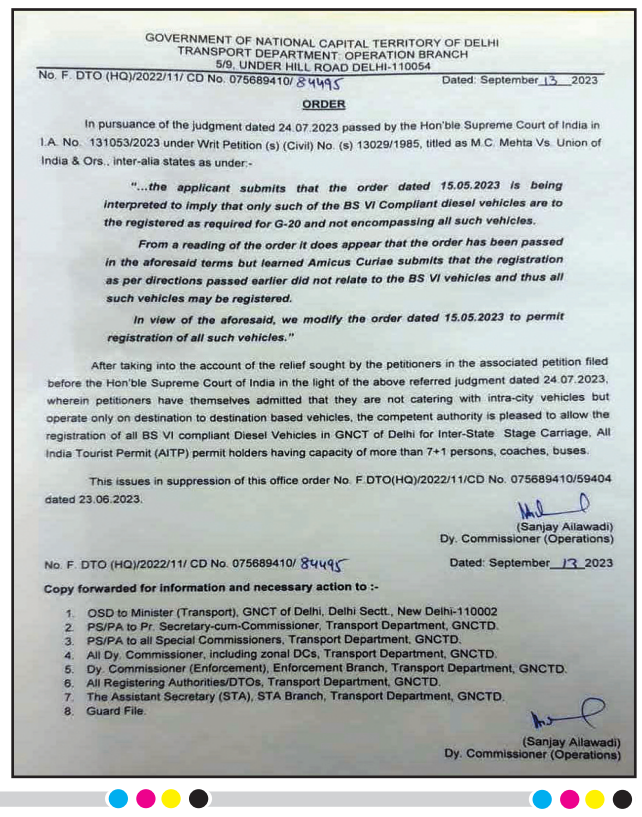

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT: OPERATION BRANCH
5/9, UNDER HILL ROAD DELHI-110054

No. F. DTO (HQ)/2022/11/ CD No. 075689410/ 84595 Dated: September 13 2023

ORDER

In pursuance of the judgment dated 24.07.2023 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in I.A. No. 131053/2023 under Writ Petition (s) (Civil) No. (s) 13029/1985, titled as M.C. Mehta Vs. Union of India & Ors., inter-alia states as under:-

"...the applicant submits that the order dated 15.05.2023 is being interpreted to imply that only such of the BS VI Compliant diesel vehicles are to the registered as required for G-20 and not encompassing all such vehicles.

From a reading of the order it does appear that the order has been passed in the aforesaid terms but learned Amicus Curiae submits that the registration as per directions passed earlier did not relate to the BS VI vehicles and thus all such vehicles may be registered.

In view of the aforesaid, we modify the order dated 15.05.2023 to permit registration of all such vehicles."

After taking into the account of the relief sought by the petitioners in the associated petition filed before the Hon'ble Supreme Court of India in the light of the above referred judgment dated 24.07.2023, wherein petitioners have themselves admitted that they are not catering with intra-city vehicles but operate only on destination to destination based vehicles, the competent authority is pleased to allow the registration of all BS VI compliant Diesel Vehicles in GNCT of Delhi for Inter-State Stage Carriage, All India Tourist Permit (AITP) permit holders having capacity of more than 7+1 persons, coaches, buses.

This issues in suppression of this office order No. F.DTO(HQ)/2022/11/CD No. 07568941O/59404 dated 23.06.2023.

(Sanjay Ailawadi)
Dy. Commissioner (Operations)

No. F. DTO (HQ)/2022/11/ CD No. 075689410/ 84595 Dated: September 13 2023

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. OSD to Minister (Transport), GNCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi-110002
2. PS/PA to Pr. Secretary-cum-Commissioner, Transport Department, GNCTD.
3. PS/PA to all Special Commissioners, Transport Department, GNCTD.
4. All Dy. Commissioner, including zonal DCs, Transport Department, GNCTD.
5. Dy. Commissioner (Enforcement), Enforcement Branch, Transport Department, GNCTD.
6. All Registering Authorities/DTOs, Transport Department, GNCTD.
7. The Assistant Secretary (STA), STA Branch, Transport Department, GNCTD.
8. Guard File.

(Sanjay Ailawadi)
Dy. Commissioner (Operations)

90 साल से अधिक जीना चाहती हैं? लंबी उम्र के ये रहे 5 रहस्य, शोध में भी हुआ खुलासा

वजन को मेंटेन रखकर आप लंबी उम्र तक जी सकते हैं. यह बात कई रिसर्च में सामने आ चुकी है. आप जीवनभर हेल्दी डाइट लें, वर्कआउट करें, मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखें तो ही आप लंबी उम्र तक जी सकती हैं. आपको ऐसी ही 5 जरूरी बातें जान लेनी चाहिए.

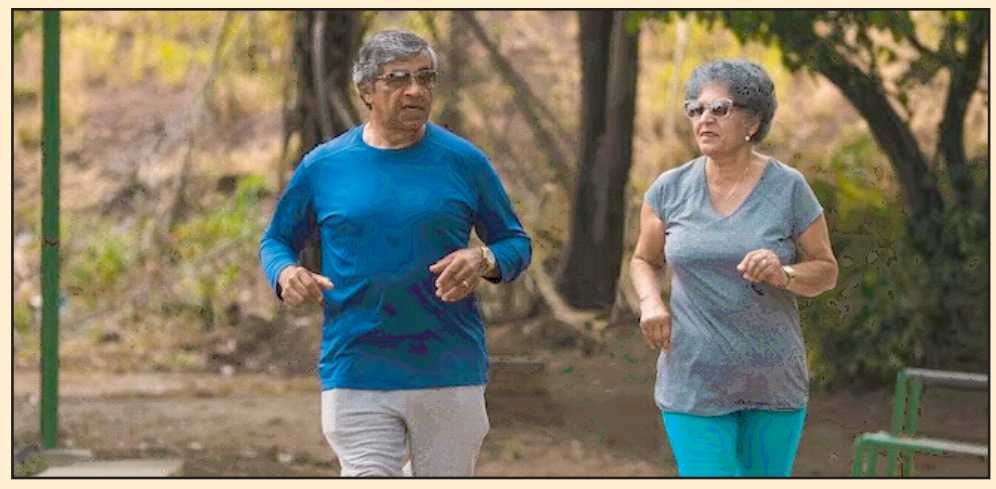

हेल्थलाइन के मुताबिक, अपने वजन को मेंटेन करने के लिए अगर आप सही डाइट लें, व्यायाम करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें, अच्छी नींद लें और सोशल सपोर्ट हासिल करें तो आपको अपने वजन को मेंटेन रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि लंबी उम्र के पीछे आपका जीन्स, इनवायरनमेंट और कई बार लक भी काम आता है, जबकि वजन में लगातार बदलाव भी लंबी उम्र को काफी प्रभावित करता है.

युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जब इस बात पर शोध किया गया कि आखिर उम्रदराज महिलाओं का उनके वजन के साथ क्या संबंध है तो पाया गया है कि उम्र बढ़ने के साथ मौत की सबसे बड़ी वजह उनमें बीमारियां मसलन हार्ट डिजीज, ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस रहा. बता दें कि इस शोध में 30 हजार से अधिक महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें 56 प्रतिशत महिलाएं 90 से अधिक उम्र तक जीवित रहीं.

इस शोध में पाया गया कि जिन महिलाओं का वजन एक जैसा रह गया, उनकी उम्र 90, 95 और 100 तक रही. बता दें कि स्टेबल वेट मेंटेन के तहत अगर महिला का वजन 5 किलो घटा तो उसे वजन घटने की कैटेगरी में रखा गया, 5 किलो वजन बढ़ गया तो उसे वजन बढ़ने की कैटेगरी में रखा गया, जबकि अगर वजन में 5 किलो के अंदर ही घटा-बढ़ा तो उसे स्टेबल वेट की कैटेगरी में गिना गया. इस तरह पाया गया कि जिनका वजन एक जैसा रह गया, उनकी उम्र लंबी रही.

उम्र दराज महिलाएं अगर अपनी उम्र को लंबा बनाना चाहती हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. हेल्दी लाइट का सेवन करें, वेजिटेबल, लीन प्रोटीन, होल ग्रेन, हेल्दी फैट का सेवन करें, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं. इसके अलावा फिजिकली एक्टिव रहें, ओवर ईटिंग से बचें, योग करें, हाइड्रेशन का ख्याल रखें, अच्छी नींद लें, डॉक्टर से चेकअप कराती रहें.

इस तरह अगर आप अपनी डाइट को लेकर सतर्क कहें, वर्कआउट करें, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने का प्रयास करें व स्मोकिंग या अल्कोहल से दूरी बनाएं तो आप अपने वजन को मेंटेन रख सकती हैं. अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है तो आप इसे मैनेज करने के तरीके अपनाएं और लोगों से मिलें-जुलें. इस तरह आपकी उम्र तो बढ़ेगी ही, आप लंबी उम्र तक एक्टिव जीवन भी व्यतीत कर सकेंगी।

30 की उम्र के बाद महिलाओं को जरूर फॉलो करना चाहिए 6 गोल्डन रूल्स, रहेंगी हेल्दी और ब्यूटीफुल

उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर टाइटनेस, ड्राइनेस, रिंकल और फाइन लाइन बनने लगती है. यही नहीं हमारी फिटनेस भी जाने लगती है. आइए जानते हैं इसका उपाय.

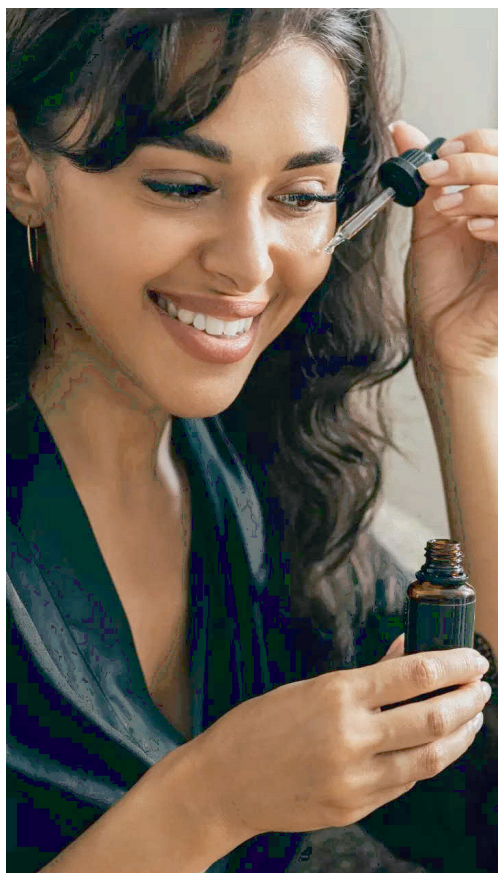

हर उम्र की महिलाओं का यह सपना होता है कि वह हमेशा खूबसूरत और फिट दिखे. लेकिन उम्र के लक्षण को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है. हालांकि अगर महिला होने के नाते अगर आप अपनी सेहत पर शुरुआती दिनों से ही ध्यान दें और अपना सही तरीके से देखभाल करें तो उम्र से पहले आप एजिंग के लक्षणों को कम कर सकते हैं. यही नहीं, अगर आप 30 की उम्र से ही अपने स्किन को लेकर सचेत रहें तो यह रिंकल और फाइनलाइन की समस्या को दूर कर सकता है. यहां हम बता रहे हैं कि आप किस तरह नेचुरल तरीके से उम्र के असर की रफ्तार को कम कर सकते हैं.

30 की उम्र के बाद इन बातों का रखें ख्याल

पानी खूब पियें

फिटडे के मुताबिक, पानी की कमी होने पर शरीर में मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है और यह स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी को प्रभावित करती है. इसलिए अपने पानी के इंटेक पर नजर रखें और भरपूर पानी पियें.

वर्कआउट करें

अगर आप 30 की उम्र के बाद भी रेग्युलर वर्कआउट करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो यह आपके आपके मसल्स को कमजोर नहीं होने देते और चेहरे व शरीर पर यूथनेस बना रहता है.

धूप से बचें

ब्रायन मावर डर्मोटोलॉजी के मुताबिक, अर्ली एजिंग का सबसे बड़ा कारण यूवी करिणें. ऐसे में रोज एसपीएफ 30 सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें और सनग्लास का प्रयोग करें.

अल्कोहल स्मोकिंग से बचें

ये दोनों ही आदतें स्किन पर रिंकल की वजह होती हैं. यह स्किन कैंसर का कारण भी बन सकता है. ऐसे में जहां तक हो अल्कोहल और स्मोकिंग से खुद को दूर रखें.

भरपूर सोएं

30 की उम्र के बाद भरपूर सोना काफी जरूरी होता है. आप कम से कम 8 घंटे की नींद रात में जरूर पूरा करें. इसके अलावा सोने और जागते समय स्किन केयर का ध्यान रखें.

हेल्दी डाइट जरूरी

स्किन को परफेक्ट रखने के लिए आप हेल्दी डाइट का सेवन करें. इसके लिए भरपूर फल, सब्जियां, अनाज आदि खाने में शामिल करें.

इस तरह आप लंबी उम्र तक खुद को फिट रख सकेंगी और हेल्दी रहने की वजह से आपकी स्किन और बालों की समस्या भी दूर रहेगी.

आप भी बनना चाहती हैं इंडिपेंडेंट, महिलाएं इन 5 चीजों पर करें फोकस, इन तरीकों से बढ़ाएं पहला कदम

कई बार महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बन पाना आसान नहीं होता है. लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट वुमेन होने की ख्वाहिश रखती हैं. तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और आत्मविश्वास जैसी चीजों पर फोकस करके आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा सकती हैं.

महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का रास्ता कई बार काफी मुश्किल होता है. ऐसे में इंडिपेंडेंट बनने के लिए ज्यादातर महिलाओं को काफी मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए किन बातों पर फोकस करना जरूरी होता है.

कई बार चाहकर भी महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम नहीं बढ़ा पाती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सी महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंट होना काफी मुश्किल भरा टास्क होता है. ऐसे में अगर आप कुछ चीजों पर फोकस करते हुए आगे कदम बढ़ाती हैं, तो आत्मनिर्भर बनने का आपका रास्ता आसान हो सकता है. तो आइये जानते हैं इसके बारे में.

सेल्फ कॉन्फिडेंस होना है जरूरी

आत्मनिर्भर बनने के लिए आपका आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है. इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये आपका पहला कदम हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फीडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करें. साथ ही प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक के डिसीजन आप खुद पूरे विश्वास के साथ लेने का प्रयास करें. इतना ही नहीं अगर कोई फैसला गलत भी होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसी और पर न डालकर आप खुद ही लें.

फैसले लेना सीखें

ज्यादातर घरों में महिलाएं हर छोटा-बड़ा फैसला घर में किसी न किसी से पूछ कर ही लेती हैं. ऐसे में उनको फैमली मेम्बर्स या पार्टनर पर निर्भर रहने की आदत हो जाती है. लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि आप खुद में डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश करें. जिससे आप जरूरत पड़ने पर खुद फैसला लेने में सक्षम रहें.

भावनात्मक रूप से मजबूत बनें

आत्मनिर्भर बनने के लिए आपका भावनात्मक रूप से मजबूत बनना भी बहुत जरूरी है. इसलिए अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहने की जगह अपनी केयर खुद करना सीखें. इस तरह से आप किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहेंगी और खुद को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रखने में कामयाब हो सकेंगी.

फाइनेंस मैनेज करना सीखें

बहुत सी महिलाएं जॉब करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहती हैं. वहीं ज्यादातर महिलाएं फाइनेंस से जुड़े डिसीजन बिना किसी की इजाजत के लेने में हिचकिचाने लगती हैं. जबकि आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि अपने बजट से लेकर इंवेस्टमेंट तक का हिसाब आप खुद रखें. इसलिए इंडिपेंडेंट बनने के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करना सीखें.

450 पुलिसकर्मियों के साथ डिनर करेंगे पीएम मोदी

G20 सम्मेलन में उत्कृष्ट काम करने वालों के मांगे गए नाम

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद हर कोई गदगद है। दिल्ली पुलिस से जुड़े अधिकारी अपने साथियों को पार्टी दे रहे हैं। सम्मेलन को सफल बनाने पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पुलिसकर्मियों के साथ डिनर करेंगे। इसके लिए पुलिस आयुक्त ने जी-20 में ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की एक सूची तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले से इनपुट का अनुरोध किया है।

नई दिल्ली। राजधानी में जी-20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) को सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों ने दिन-रात काम किया। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस हर मौके पर मुस्तैद रही है। जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इसी हफ्ते दिल्ली पुलिस के कर्मियों के साथ डिनर करेंगे।

30 से अधिक देश ने लिया हिस्सा

दिल्ली में दो दिवसीय जी-20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 30 से अधिक नेताओं, शीर्ष यूरोपीय संघ के अधिकारियों, अतिथि देशों के प्रतिनिधियों और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। जी-20 सम्मेलन के आयोजन की सुरक्षा-व्यवस्था में 50 हजार से अधिक कर्मियों की तैनाती थी। इसमें डॉग स्क्वॉड और घुड़सवार पुलिस जैसी विशेष इकाइयाँ भी शामिल थीं।

पुलिसकर्मियों के साथ पीएम मोदी करेंगे डिनर

अब सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री ने आगामी 16 सितंबर को प्रगति मैदान के भारत मंडपम मंडपम में दिल्ली पुलिस के साथ डिनर करने का निर्णय किया है। डिनर में करीब 450 पुलिसकर्मी (सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर) शामिल होंगे। देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ डिनर करेंगे।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक जी-20 में सुरक्षा यूनिट, यातायात, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, विजिलेंस, आर्थिक अपराध शाखा समेत सभी 15 जिले व सीपी रिजर्व आदि के पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। सबसे अधिक सुरक्षा यूनिट व ट्रैफिक यूनिट के कर्मियों को लगाया गया था।

पीएम कार्यालय से उन कर्मियों की सूची मांगी गई है जिन्होंने लंबे समय तक जी 20 की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली और कड़ी मेहनत के जरिए बेहतर से जिम्मेदारी को निभाया। सबसे अधिक सुरक्षा व ट्रैफिक यूनिट के कर्मियों को जी-20 में लगाया गया था। ऐसे में इन दोनों यूनिटों के सबसे अधिक कर्मियों को डिनर में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा। ट्रैफिक यूनिट से 10 हजार कर्मियों को ट्रैफिक के संचालन में लगाया गया था।

इस यूनिट के 50 कर्मियों के नाम भेजे गए हैं। सुरक्षा प्रबंधन में विशेष आयुक्त मधुप तिवारी, एसएस यादव, रवींद्र सिंह यादव, एचजीएस धालीवाल, सागर प्रीत हुड्डा, दीपेंद्र पाठक, सतीश गोलचा, शालिनी सिंह, संयुक्त आयुक्त भोला शंकर जायसवाल, परमादित्य, छाया शर्मा, विवेक किशोर, विक्रमजीत सिंह, चिन्मय बिस्वाल, मधुर वर्मा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा, रोमिल बानिया, डीसीपी संजय कुमार सेन, मनोज सी, प्रणय तायल, मनीषी चंद्रा, रवि कुमार सिंह, सागर सिंह कलसी, हरेंद्र कुमार सिंह, कुमार ज्ञानेश, सुमन नलवा, देवेश महला आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिसकर्मियों को दो दिन की छुट्टी देने की बात

इससे पहले सोमवार को आयुक्त की ओर से उनके ओएसडी डीसीपी मनीषी चंद्रा ने सभी 15 जिलों व यूनिटों के डीसीपी को पत्र जारी कर कहा है कि वे अपनी-अपनी सुविधा अनुसार जगह व तारीख तय कर अपने-अपने कर्मियों को बड़ा खाना (दावत) दें। पुलिस आयुक्त की ओर से धन्यवाद के प्रतीक के रूप में दावत का आयोजन किया जाएगा। जिले व यूनिटों के डीसीपी को जारी दूसरे पत्र में मनीषी चंद्रा ने कहा है कि जी-20 की सुरक्षा में शामिल सभी कर्मियों को वे दो-दो दिन का अवकाश दें। हर दिन करीब 10 प्रतिशत कर्मियों को अवकाश दें, ताकि अगले 10 दिनों में सभी को यह सुविधा मिल सके।

दिल्ली में सबसे कम महंगाई दर, राघव चड्ढा बोले- सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल्याणकारी मॉडल दिया...

देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राघव चड्ढा ने कहा कि पूरे देश में किसी राज्य में महंगाई से कहीं राहत है तो वह दिल्ली है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत महंगाई 6.83 प्रतिशत है वहीं दिल्ली में आधे से कम तीन प्रतिशत है। अरविंद केजरीवाल ने एक कल्याणकारी मॉडल दिया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कल्याणकारी मॉडल दिया है। मैं इसे अरविंद केजरीवाल महंगाई राहत मॉडल कहूंगा, जिसके तहत लोगों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी उपलब्ध है।

नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को कहा कि पूरे देश में किसी राज्य में महंगाई से कहीं राहत है तो वह दिल्ली है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत महंगाई 6.83 प्रतिशत है, वहीं दिल्ली में आधे से कम तीन प्रतिशत है।

मोदी सरकार में महंगाई जानलेवा है- आप

राघव चड्ढा ने 'सखी सैंया तो खूब ही कमात है महंगाई डायन खाए जात है' का जिक्र करते हुए कहा कि ये गाना आज देश की आधी से ज्यादा आबादी के कानों में गूंज रहा है। मोदी सरकार में महंगाई जानलेवा है। दवाई से लेकर पढ़ाई तक सब महंगा हो गया है।

पूरे देश में दिल्ली में महंगाई से राहत

अंग्रेजों ने जिन चीज़ों पर कभी टैक्स नहीं लगाया, उन आटा, दाल, चावल, दूध, दही पर मोदी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। आप सांसद ने कहा कि पूरे देश में किसी राज्य में महंगाई से कहीं राहत है तो वह दिल्ली है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत महंगाई 6.83% है, तो दिल्ली में तीन प्रतिशत है, जोकि आधे से भी कम है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ढाल बनकर मोदी सरकार के बाण रोके हैं।

रेवड़ी नहीं, प्रीपेड सेवाएं - राघव चड्ढा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कल्याणकारी मॉडल दिया है। मैं इसे अरविंद केजरीवाल महंगाई राहत मॉडल कहूंगा, जिसके तहत लोगों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी उपलब्ध है। चड्ढा ने कहा कि बीजेपी कल्याणकारी योजनाओं को 'रेवड़ी' कहती है।

उन्होंने कहा कि ये रेवड़ी नहीं बल्कि प्रीपेड सेवाएं हैं। लोग इन सेवाओं के लिए टैक्स देते हैं। अरविंद केजरीवाल इन योजनाओं के माध्यम से आपका पैसा वापस देते हैं। बता दें कि मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत को छूने के बाद अगस्त में घटकर 6.83 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में नरमी है।

मॉटो जीपी भारत: 119 किमी., 24 लैप, 360 की स्पीड का रोमांच; बीआईसी की खासियतें जहां 22-24 सितंबर को बनेंगे कई रिकॉर्ड

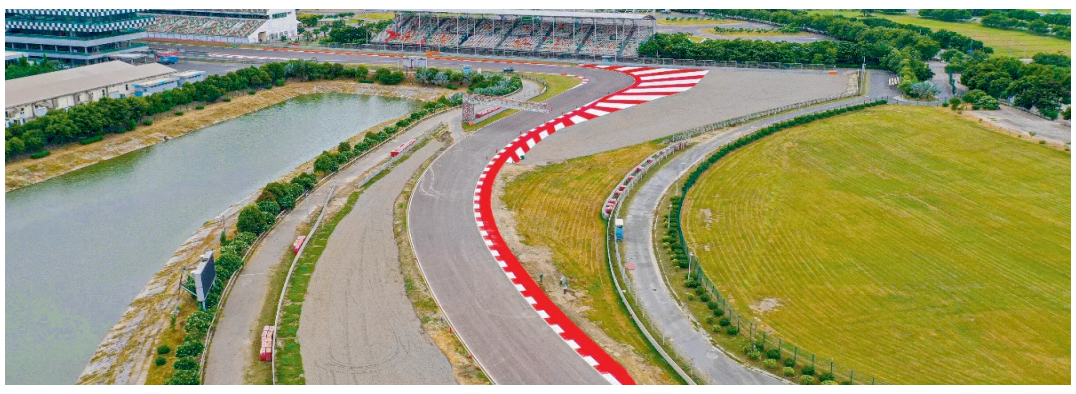

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) (Buddh International Circuit) में 22 से 24 सितंबर तक रफ्तार के शौकीनों को दुनिया की सबसे तेज बाइक को दौड़ते और इंजन की गड़गड़ाहट अलग की रोमांच भर देगी। मोटोजीपी भारत की मुख्य रेस के साथ ही दर्शकों को मोटो3 और मोटो2 रेस भी देखने का मौका मिलेगा। 24 सितंबर को मोटोजीपी की मुख्य रेस 24 लैप (चक्कर) की होगी।

ग्रेटर नोएडा। मोटोजीपी भारत को अब 10 दिन शेष रह गए हैं। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) में 22 से 24 सितंबर तक रफ्तार के शौकीनों को दुनिया की सबसे तेज बाइक को दौड़ते और इंजन की गड़गड़ाहट अलग की रोमांच भर देगी।

मोटोजीपी भारत की मुख्य रेस के साथ ही दर्शकों को मोटो3 और मोटो2 रेस भी देखने का मौका मिलेगा। 24 सितंबर को मोटोजीपी की मुख्य रेस 24 लैप (चक्कर) की होगी। साढ़े पांच किलोमीटर लंबे सर्किट पर 118.97 किलोमीटर की दूरी बाइक तय करेंगी। 22 सितंबर को मोटो 3 और 23 सितंबर को मोटो2 रेस होगी।

मोटोजीपी, मोटो2 और मोटो3 में काफी अंतर

मोटोजीपी मुख्य रेस होती है जिसमें बाइक का इंजन एक हजार सीसी का इंजन होता है और इनकी अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रतिघंटा की होती है। मोटो2 में 765 सीसी इंजन की बाइक दौड़ती हैं और मोटो3 में 250 सीसी की बाइक रेस में हिस्सा लेती हैं। मोटोजीपी भारत में मोटो3 रेस 17 लैप की होगी, जिसकी कुल दूरी 84.27 किमी और मोटो2, 19 लैप की होगी जिसमें कुल दूरी 94.18 किमी होगी। सभी की बाइक के इंजन का कंबशन 4 स्ट्रोक होता है।

स्पीड का नया रिकार्ड के गवाह बनने को तैयार सर्किट

इस साल रेड बुल केटीएम के ब्रैड बाइंडर ने 366.1 किमी प्रति घंटा का हाई-स्पीड रिकार्ड बनाया है। बीआइसी में 1006 मीटर की लंबी बैक स्ट्रेट है। यही कारण है कि मोटोजीपी भारत में लगभग 370 किमी/घंटा तक की स्पीड पहुंचने की उम्मीद है।

दो भागों में बंटा है स्ट्रेच

इस सीधे स्ट्रेच को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्ट्रेच ढलान पर है, जो राइडर्स को अधिकतम स्पीड प्राप्त करने में मदद करेगा। दूसरा स्ट्रेच, ऊपर की ओर है, उन्हें देर से ब्रेक लगाने और टाप स्पीड बनाए रखने में मदद करेगा।

मोटोजीपीटीएम के प्रमोटर्स व फेयरस्ट्रीट स्पोर्ट्स के रेसिंग निदेशक अमित सांडिल्य ने बताया कि टर्न 9 और 10 पर स्थित पाराबोला या स्टेडियम सेक्शन, राइडर्स को अपनी बाइक को रफ्तार की अधिकतम स्पीड तक ले जाने में मदद करेगा। 1800 मीटर नई सुरक्षा बैरिकेडिंग बनाने के साथ सुरक्षा उपायों को भी मजबूत किया गया है।

13 चुनौतीपूर्ण मोड़

डोर्ना स्पोर्ट्स के मुख्य खेल अधिकारी कार्लोस एज्पलेटा ने बताया कि ट्रेक में 13 चुनौतीपूर्ण मोड़ जिसमें आठ दाएं और पांच बाएं मोड़ शामिल हैं। डुकाटी के फ्रांसेस्को बगानिया, रेप्सोल होंडा टीम के मार्क मार्केज, मूनी के मार्को बेजेची, रेड बुल केटीएम के ब्रैड बाइंडर और जैक मिलर, प्राइमा के जार्ज मार्टिन सहित रेसिंग जगत के कुछ सबसे बड़े नाम मोटोजीपी भारत में भाग लेंगे।

शिक्षाविदों ने हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने की अपील की

हिंदी महज भाषा नहीं बल्कि देश में अनेकता में एकता का स्वरूप इसी से तय होता है। इसलिए हिंदी को राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। हिंदी दिवस पर दैनिक जागरण के अभियान 'हिंदी हैं हम' के अंतर्गत दिल्ली संवादी का आयोजन किया गया। अभिव्यक्ति के इस उत्सव में भाषा और साहित्य से जुड़े लेखक शिक्षाविद और संस्कृतिकर्मी अलग अलग सत्र में जुड़े।

नई दिल्ली। हिंदी महज भाषा नहीं, बल्कि देश में अनेकता में एकता का स्वरूप इसी से तय होता है। इसलिए हिंदी को राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। हिंदी दिवस पर दैनिक जागरण के अभियान 'हिंदी हैं हम' के अंतर्गत दिल्ली संवादी का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर अभिव्यक्ति के इस उत्सव में भाषा और साहित्य से जुड़े लेखक, शिक्षाविद और संस्कृतिकर्मी अलग अलग सत्र में जुड़े।

इस दौरान जागरण हिंदी बेस्टसेलर की घोषणा भी की गई। इसमें कथा, कथेतर, कविता और अनुवाद की चार श्रेणियों में सबसे अधिक बिकने वाली 35 पुस्तकों की सूची जारी की गई। इस सूची को विश्व प्रसिद्ध एजेंसी नील्सन ने तैयार किया है।

हिंदी को राष्ट्राभाषा का दर्जा देने की मांग

नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में दीप प्रज्वलन के साथ चार सत्रों में चले जागरण संवादी में तमाम वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान हिंदी को राजभाषा के बदले राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा। उद्घाटन सत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा हुई।

भविष्य और साहित्य सत्र के दौरान साहित्य अकादमी के सचिव ड. के एस राव, लेखिका क्षमा शर्मा, केंद्रीय हिंदी संस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल जोशी। (बाएं से दाएं)।

इसमें दैनिक जागरण के कार्यकारी संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी और केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक सुनील कुलकर्णी ने अपने विचार रखे। पहले सत्र का विषय साहित्य और दिल्ली था। इसमें लेखक व दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति प्रो. सुधीश पचौरी, लेखक व रेलवे बोर्ड के पुर्व संयुक्त सचिव प्रेमपाल शर्मा और साहित्य अकादमी से सम्मानित बाल साहित्यकार दिविक रमेश वक्ता रहे। दूसरे सत्र में भारत का भविष्य और साहित्य पर साहित्य अकादमी के सचिव डॉ. केएस राव, लेखिका क्षमा शर्मा और वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष अनिल जोशी ने विस्तृत चर्चा की। तीसरे सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी पर चर्चा हुई। इस सत्र में लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुरली मनोहर पाठक, एनआईईपीए की कुलपति प्रो. शशिकला वंजारी व राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की अध्यक्ष प्रो. सरोज शर्मा से प्रो. रवि प्रकाश टेकचंदाणी ने संवाद किया।

अवंतिका मार्किट में दिवाली पर चला पीला पंजा

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। रोहिणी के सेक्टर-1 अवंतिका मार्किट पर बुधवार को एमसीडी के पीले पंजे समेत भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच दुकानों से बाहर तक के एंकरोचमेंट को हटा दिया गया। ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी हद से बाहर फुटपाथ तक पर कब्जा कर लिया था। एमसीडी के अधिकारी के मुताबिक फुटपाथ को घेरे जाने से पैदल चलने वालों को बामुश्किल चलती रोड पर से होकर चलना पडता है। इस बावत अवंतिका मार्किट दुकानदारों को कई बार चेतावनी दी चुकी है। बावजूद इसके दुकान से बाहर पांच से छह फुट जगह पर एंकरोचमेंट से पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही थी। नाम ना छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि एंकरोचमेंट को हटाने संबंधी हाई कोर्ट के आर्डर भी आ चुके हैं। और एमसीडी भी नोटिस दे चुकी है। बुद्धवार को इसी के मद्देनजर ही एमसीडी ने अपने पूरे लाव लश्कर - पुलिस फोर्स के साथ एंकरोचमेंट हो हटाया गया है। इसके अलावा अवंतिका के बी-सी ब्लाक के बीच की सडक पर बनी सब्जी मंडी पर भी पीले पंजे ने सफाया कर दिया। हालांकि एमसीडी ने सब्जी मंडी को उजाड़ने की कारवाई को पहले भी अंजाम दिया है। लेकिन सब्जी मंडी बी-सी ब्लाक की सडक के दोनों ओर बदस्तूर जारी है। इस बावत अवंतिका व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय पाल ने एमसीडी की इस कार्रवाई पर अपना विरोध प्रकट किया है। अध्यक्ष का कहना है कि दिवाली से पहले व्यापारी अपनी सेल के तहत ग्राहकों को आकृषित करने के लिए कपडों का प्रदर्शन करना एंकरोचमेंट नहीं है। दुकान बंद करने से पहले सब सामान को हटा लिया जाता है। ऐसा कोई स्थाई कब्जा कहीं भी नहीं है। एमसीडी ने तो दुकान के बोर्ड, शेड एंगल तक को नहीं बख्शा है। वैसे भी इन दिनों मंदी की मार है। कोरोना के कहर से दुकानदार अब तक नहीं उबर पाया है। दुकानदार एमसीडी, प्रशासन को हर तरह के टैक्स की अदायगी के बाद भी सुरक्षित नहीं है।दुकानदारों, व्यापारियों को त्यौहारी मार से प्रशासन को सहयोग करना चाहिए ना के उजाडना चाहिए।

रोहिणी के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के फरार बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के सभी बैंक खाते सील:हाईकोर्ट

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। रोहिणी के सैक्टर -5 के विजय विहार फेज-1 में स्थित अवैध आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में महिलाओ और नाबालिग बच्चियों के यौन शौषण के आरोपी संचालक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के 7साल बाद सभी बैंक खाते सीज करने के निर्देश दिए है। बता दें कि साल 2017 में महिलाओ और नाबालिग बच्चियों के कथित शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न के मामले उजागर होने के बाद सुर्खियों में आए 72 वर्षीय बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर अब 7 साल बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को बैंक खाते सीज करने की इजाजत दे दी है। इस मामले में कई महिला संगठनों ने आश्रम के बाहर धरना-प्रदर्शन कर ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करने की मांग की थी। मामले की गंभीरता के मद्देनजर ही पुलिस से मामले को लेकर सीबीआई को केस ट्रांसफर करना पडा था। और बाबा दीक्षित की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए थे। कथित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित मामले के उजागर होने के बाद से लापता है। हालांकि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से वह राजस्थान ,दिल्ली समेत अन्य स्टेटों में आश्रम अब भी चला रहा है। पुलिस उसको पकडने के लिए दंबिश दे रही है। बताया जाता है कि बाबा की पीठ पर सियासती हाथ है। इसी लिए उसको सीबीआई अब तक नहीं ढूंढ पाई है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने सीबीआई द्वारा पेश स्टेट्स रिपोर्ट में कोर्ट को बताया कि उसने अब तक आरोपी बाबा दीक्षित को गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाए है ।दरअसल वह कई आपराधिक मामलों में आरोपी है ।यह मामला तब नाबालिग बेटी के परिवार ने ही दर्ज करवाया था। उनका बाबा पर आरोप था कि बाबा ने उनकी नाबालिग लडकी को आश्रम में बंधक बनाकर रखा है। लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि बेटी अब बालिग है। वह उनके साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते है। लिहाजा सीबीआई को अपनी जांच करने दें।

महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 पवनानंद गिरी जी होंगे महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से सम्मानित

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र रत्न अवॉर्ड से महान संत एवं समाज सेवी श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर पवनानंद गिरी जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा। 13वां महाराष्ट्र रत्न अवॉर्ड से महामंडलेश्वर को सम्मानित करने की घोषणा से संत समाज एवं उनके भक्तों में काफी उत्साह एवं खुशी की लहर है। आगामी 15 सितंबर को मयूर हाल (बीएमडब्ल्यू शोरूम के समीप) जुहू रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान महामंडलेश्वर श्री पवनानंद गिरि जी महाराज को महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसका आयोजन अंजन गोस्वामी और श्रीमती अनीता ए. गोस्वामी के द्वारा किया गया है। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर पवनानंद गिरि जी महाराज श्री श्री अयोध्या धाम पीठाधीश्वर के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं तथा अपने संत संस्कार एवं सेवा भाव से काफी ख्याति प्राप्त की है। अपने घर परिवार को छोड़कर वह भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित है तथा मानवता की सेवा ही उनका मुख्य लक्ष्य है। इस दिशा में वह लगातार कई ऐसे काम किए हैं जो समाज एवं व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। यही कारण है कि महामंडलेश्वर पवनानंद गिरी जी महाराज को 13 में महाराष्ट्र रत्न अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। इससे संत समाज का मन बड़ा है तथा उनके भक्तों में काफी खुशी है।

जीआईसी मैदान में, अंगदान शपथ महाशिविर 16 सितम्बर को

विकास भवन सभागार में केन्द्रीय मंत्री प्रो.एस पी सिंह बघेल की अध्यक्षता में तैयारियों हेतु समीक्षा बैठक संपन्न

- पीएम मोदी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आगरा में 7300 लोगों से अंगदान की शपथ कराएंगे केन्द्रीय मंत्री प्रो . एस . पी . सिंह बघेल
- कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ . मनसुख मंडाविया तथा नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन (NOTTO) के अधिकारी रहेंगे उपस्थित, वर्चुअल और वीडियो संदेश से जुड़ेंगे मा . प्रधानमंत्री मोदी जी तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ
- वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पर 13 अगस्त को मा . केंद्रीय मंत्री बघेल अपने 07 अंगों को अंगदान कर बने प्रेरणा स्रोत, मा . मंत्री के परिवार ने भी किया है अंगदान
- भारत, ऋषि दधीच की धरती, मानवता के कल्याण हेतु यहां अंगदान और देहदान की रही है परंपरा, मा . मंत्री ने सभी जनपद वासियों,धार्मिक,सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आमजन से की, कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर अंगदान और देहदान करने की अपील
- आगरा दानवीरों की धरती, यहां सबसे ज्यादा डोनेशन और परोपकार के होते हैं कार्य,कार्यक्रम में अंग दान और देहदान की शपथ लेकर देश में जनपद और शहरवासी बनाएं नजीर
- अंगदान की शपथ लेने के लिए आधार कार्ड तथा वही मोबाइल नंबर साथ लाएं जो आधारकार्ड से लिंक हो, जिससे कि ओटीपी प्राप्त किया जा सके

मयूर खान

आगरा। केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जीआईसी मैदान, आगरा पर 16 सितंबर 2023 को प्रस्तावित अंगदान शपथ महाशिविर संबंध में तैयारियों हेतु समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने अंगदान महाशिविर का की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि एक व्यक्ति मरणोपरांत आठ लोगों को जीवन दे सकता है। अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। उन्होंने आह्वान किया कि हम 16 सितम्बर को प्रातः दस बजे से लेकर दो बजे के मध्य जीआईसी मैदान पर आएं और इस मुहिम का हिस्सा बनें। ये एक ऐसा काम है जो महान ही नहीं, महानतम है।

उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि शरीर मरणोपरांत कुछ देर में ही ख़ाक में मिल जाना है। अगर वो शरीर का कोई अंग किसी के काम आ जाए या किसी का जीवन उसके किसी अंग से बच जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अंगदान का जो प्रमाण पत्र मिलेगा, उसे फ्रेम कराकर अपनी बैठक में लगा लें। समय समय पर अपने परिवार को ये बताते रहे हैं कि मेरे मरने के बाद शरीर दान दे दें। इससे मेरी आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी। मा. मंत्री ने बताया कि वे इस बात में यकीन रखते है कि किसी भी व्यक्ति से कुछ करने के लिए कहने से पहले हमें उस कार्य को खुद में आत्मसात करना चाहिए,इसीलिए सर्व प्रथम मैंने लोगों से अंगदान की अपील करने से पहले स्वयं अंग दान करने की शपथ ली। बैठक में उन्होंने बताया कि मनुष्य के कई सारे अंगों का दान किया जा सकता है। यह सिर्फ हृदय, लिवर और गुर्दे का दान नहीं होता। पैनक्रियाज, फेंफड़े, छोटी और बड़ी आंत,त्वचा, हड्डी, हार्ट वाल्व और टेंडन जैसे टीश्यूज को भी दान कर सकते हैं। दान किया हुआ यह अंग किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसके लिए दानदाता के शरीर से दान किए गए अंग को ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है। अंगदान के मामलों को राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) देखता है। उन्होंने बताया कि अंगदान की शपथ लेने के लिए आधार कार्ड तथा वही मोबाइल नंबर साथ लाएं जो आधारकार्ड से लिंक हो, जिससे कि ओ टी पी प्राप्त किया जा सके।

उन्होंने 16 सितंबर को सभी से कोई एक अंग दान करने की शपथ लेने का आह्वान किया।

बैठक में जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी, सीडीओ ए. मनिकंडन, डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य अनूप कुमार, सीएमओ अरुण श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी,नगर अनूप कुमार, सभी जनपद स्तरीय अधिकारी समस्त खंड विकास अधिकारी, सीएचसी, पीएचसी प्रभारी सहित नवीन गौतम, पार्षद गौरव शर्मा आदि मौजूद रहे।

स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करने के लिए रंजीत एवेन्यू में एक विशेष रैली की

अमृतसर (साहिल बेरी)। जिस पर मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के लोगों से बात की और बताया कि पंजाब सरकार उनकी सभी बढ़ोतरी को पूरा करेगी और पंजाब के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी ।एलए डॉ. जसबीर सिंह संधू जी अपने पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ रंजीत एवेन्यू में वार्ड नंबर 74 नवी 68 के एक मेहनती सेवादार सरदार शमशेर सिंह संधू जी के साथ दो बसों और पांच कारों और मोटरसाइकिलों में अपने क्षेत्र के निवासियों की एक बड़ी सभा के साथ भाग लिया। सरदार भगवंत सिंह युवा सवार के साथ मांजी के विचार सुनने रंजीत एवेन्यू पहुंचे

पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राज्य में रखी शिक्षा क्रांति की नींव, पहले 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' का लोकार्पण किया

साहिल बेरी

अमृतसर। विद्यार्थियों के जीवन में ऊंचाई छूने के सपनों को उड़ान दे रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य का पहला 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' पंजाब के लोगों को समर्पित किया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा, "पंजाब में आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है और ये स्कूल निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होंगे." मुख्यमंत्रियों ने कहा कि आज एक यादगार अवसर है और वह दिन दूर नहीं जब पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से विद्यार्थियों, विशेषकर गरीब एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी. उन्होंने कहा कि इन स्कूलों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र जल्द ही हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे और राज्य का नाम रोशन करेंगे. दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि ये स्कूल हमारे छात्रों की किस्मत बदल देंगे. उन्होंने कहा कि

यह सिर्फ शुरुआत है और गरीब छात्रों के कल्याण के लिए ऐसे और स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये स्कूल 'आधुनिक युग के मंदिर' होंगे जो छात्रों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने स्कूलों की कक्षाओं का दौरा किया और छात्रों से बातचीत की. सरकार के इस दूरदर्शी कदम के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए 11वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा ने कहा कि पहले वह एक निजी स्कूल में पढ़ती थी. उस छात्र ने कहा कि इस स्कूल में जो सुविधाएं मिलती हैं वह इन प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलती. उन्होंने इस स्कूल की स्थापना के लिए भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया। परीक्षा पास करने के बाद इस स्कूल में दाखिला लेने वाली एक अन्य छात्रा किरणदीप कौर ने कहा कि वह सीमावर्ती इलाके के एक गांव की रहने वाली है और डॉक्टर बनना चाहती है. उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यह इच्छा पूरी होना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब उन्हें यकीन है कि इस स्कूल की बदौलत उनका सपना जल्द ही पूरा होगा। उन्होंने युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने वाली इस नेक पहल के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया।

सीएचसी में एमएनसीयू वार्ड का मंत्री ने किया उद्घाटन

कैबिनेट मंत्री ने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली

- गोद भराई की रस्म कराई, साथ ही अन्नप्राशन करते हुए पोषण किट बांटी

मयूर खान, आगरा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिचपुरी आगरा में सोमवार को मदर-न्यू बोर्न केयर यूनिट (एमएनसीयू) वार्ड का उद्घाटन महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की मंत्री बेबीरानी मौर्या ने किया। कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की।

उद्घाटन के बाद कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबीरानी मौर्या ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। एकीकृत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस) विभाग द्वारा गोद भराई व अन्नप्राशन के कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की। इसके बाद कभवारी की पल्लवी व इरा का अन्नप्राशन कराया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी आदीश मिश्रा ने बताया कि बच्चों, किशोर-किशोरी, गर्भवती व धात्री महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विटामिन, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों का मिलना बहुत जरूरी होता है। पुष्टाहार के साथ-साथ हरी सब्जियों के सेवन से इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। इसी क्रम में एकीकृत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस) विभाग द्वारा जनपद के प्रत्येक ब्लॉक के लगभग सभी ग्राम पंचायतों में पोषण वाटिकाएं तैयार की गई हैं। पोषण वाटिका को तैयार करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने अपना पूरा योगदान दिया है।

इस मौके पर किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष व मंत्री के प्रतिनिधि यशपाल राणा, भाजपा के युवा नेता अभिनव मौर्या, ब्लॉक प्रमुख बिचपुरी आगरा सोनू दिवाकर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पीके शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक बिचपुरी डॉ.राजवीर सिंह, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक लोकेंद्र तिवारी, आईसीडीएस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, आशा संगिनी सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिचपुरी समस्त स्टॉफ मौजूद रहा।

इनकी हुई गोद भराई

-अमरपुरा निवासी सोनिया व किरन, महारानी बाग की बबली, अंगूठी की भारती व किरन और अंजलि की गोद भराई की रस्म हुई।

बच्चों को मिली पोषण किट

कार्यक्रम के दौरान श्रीमती बेबीरानी मौर्य ने बिचपुरी की काव्या, उज्ज्वल, अंगूठी की नित्या, लड़ामदा की अंशू व नानपुर की वर्षा को कुपोषण दूर करने के लिए पोषण किट प्रदान की।

सपेरों ने बीन बजाकर कमिश्नर कार्यालय पर दिया धरना, आर्थिक मुआवजे की उठाई मांग

मयूर खान, आगरा। सोमवार को सपेरा समाज ने आगरा मंडलायुक्त कार्यालय पर अनोखा प्रर्दशन किया। भारी संख्या में सपेरा समाज के लोग मंडलायुक्त कार्यालय पहुँचे और वहीँ पर धरना शुरू कर दिया। लोगों ने बीन बजाना शुरू कर दिया जिससे कि उनकी मांग और समस्या मंडलायुक्त के कानों तक पहुंच जाए और फिर सरकार भी उनकी मांगों पर ध्यान दे।

पुश्तैनी कार्य से रोके जाने से नाराज

जानकरी के मुताबिक नए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सांपों को पकड़ना और उसका खेल दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है। सपेरा समाज के लोगों का कहना है कि सांपों का खेल दिखाना उनका पुश्तैनी काम है। इस पर प्रतिबंध लग जाने से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। अगर सरकार ऐसा ही करना चाहती है तो उन्हें नौकरी दी जाए या फिर कोई काम शुरू करने के लिए समाज के लोगों को 5-5 लाख रुपए सहायता दी जाए।

कुछ सपेरों पर हुई थी कार्यवाही

कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन ने सपेरा समुदाय के कुछ लोगों पर कार्रवाई की है। सांपों का खेल दिखा रहे सपेरों को पकड़कर उन्हें जेल भेज दिया और सांपों को जंगल में छोड़ दिया। प्रशासन की कार्रवाई से भी सपेरा समाज आहत है और प्रशासन से जेल भेजे गए सपेरा समाज के लोगों को रिहा करने की मांग कर रहे है। सपेरा समाज के लोगों का कहना है कि सरकार उन्हें एससी-एसटी का दर्जा दे जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त हो सके। उनका अधिकतर समाज और बच्चे अशिक्षित हैं। अगर ऐसा होता है तो समाज के लोग बच्चों को शिक्षित बनाने पर जोर देंगे और वह अपने इस पुश्तैनी कार्य को भी छोड़ पाएंगे।

बेहतर ट्रैफिक, बेहतर भोपाल

भोपाल। मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के अंतर्गत सुभाष नगर रेल्वे अंडर ब्रिज एवं स्लॉटर हाउस के बीच मेट्रो स्टेशन के फाउण्डेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसके कारण जिंसी धर्म कांटा से सुभाष नगर अण्डर ब्रिज तक रोड बंद किया जाकर यातायात डायवर्सन करने की समयावद्धि बढाने की सूचना निर्माण कंपनी द्वारा यातायात पुलिस को दी गई हैं।

सुरक्षित यातायात के दृष्टिकोण से निर्माण कार्य के दौरान दिनांक 11.10.2023 तक यातायात डायवर्सन प्लान निम्नानुसार रहेगा।

01. जिंसी धर्म कांटा से सुभाष रेल्वे अण्डर ब्रिज तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा।

02. हल्के वाहन/दुपहिया/चार पहिया- लिलि टॉकीज एवं बोगदा पुल से जिंसी धर्म कांटा होकर मैदा मिल की ओर जाने वाले वाहन बोगदा पुल, प्रभात चैराहा, सुभाष नगर अण्डर ब्रिज एवं सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज होकर मैदा मिल की ओर जा सकेंगे।

इसी प्रकार मैदा मिल से लिलि टॉकीज एवं बोगदा पुल की ओर जाने वाले वाहन मैदा मिल, सुभाष नगर अण्डर ब्रिज, सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज, प्रभात चैराहा, बोगदा पुल व लिलि टॉकीज की ओर जा सकेंगे।

03. भारी व मध्यम वाहन/सभी बसें/अनुमति प्राप्त वाहन- लिलि टॉकीज एवं बोगदा पुल से जिंसी धर्म कांटा होकर मैदा मिल की ओर जाने वाले वाहन बोगदा पुल, प्रभात चैराहा एवं सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज होकर मैदा मिल की ओर जा सकेंगे। इसी प्रकार मैदा मिल से लिलि टॉकीज एवं बोगदा पुल की ओर जाने वाले वाहन मैदा मिल, सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज से प्रभात चैराहा, बोगदा पुल व लिलि टॉकीज की ओर जा सकेंगे।

वाणिज्य,स्टांप रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन,नगरीय विकास, खनिज विभाग इत्यादि के लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर जताई कड़ी नाराजगी

मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में कर- करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक संपन्न

मयूर खान

आगरा। मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में कर-करेत्तर व राजस्व वसूली की मंडलायुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

बैठक में सर्व प्रथम वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की गई, मंडलायुक्त द्वारा जानकारी करने पर बताया गया कि अगस्त माह तक 40 प्रतिशत वसूली लक्ष्य के सापेक्ष होनी चाहिए लेकिन मंडल में लक्ष्य के सापेक्ष 30 प्रतिशत वसूली होने पर मंडलायुक्त द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई, स्टांप रजिस्ट्रेशन की समीक्षा में मंडलायुक्त द्वारा मंडल की प्रदेश स्तर पर रैंकिंग पूछे जाने पर बताया गया कि मंडल 13वें स्थान पर है,वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक उपलब्धि में मंडल में सर्वाधिक खराब स्थिति जनपद मैनपुरी, प्रदेश स्तर पर 75 वें स्थान पर रही, लक्ष्य के सापेक्ष आगरा 30.39 प्रतिशत, फिरोजाबाद 32.95 प्रतिशत, तथा मथुरा का प्रदेश में छठवां स्थान रहा।मंडलायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया जनपद मैनपुरी कि पूरे मंडल की प्रदेश स्तर पर मंडल की रैंकिंग खराब कर रहा, उन्होंने सर्किल रेट युक्तियुक्त पूर्ण बढ़ाने लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश दिए।

बैठक में आबकारी विभाग की समीक्षा में बताया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक उपलब्धि में आगरा 29.42 प्रतिशत, फिरोजाबाद 28 , मथुरा 30 तथा मैनपुरी 30 प्रतिशत रहा तथा प्रदेश स्तर पर मंडल की 6वीं रैंक है, मंडलायुक्त ने लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने को निर्देशित किया। परिवहन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि माह जून में मंडल 18 वें स्थान से सुधार कर 13 वें स्थान पर है तथा मासिक लक्ष्य के अनुरूप 5वें नंबर पर है, मंडलायुक्त महोदया द्वारा जिन वाहनों के 15 वर्ष पूर्ण होने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं उन सभी का डाटा स्मार्ट सिटी के आईटीएमएस सिस्टम पर अपडेट करने के निर्देश दिए जिससे कि उक्त वाहन चिह्नित कर प्रभावी कार्यवाही की जा सके तथा सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मंडलायुक्त महोदया द्वारा बैठक में आरसी वसूली की समीक्षा की, आरसी वसूली में शिथिलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा मंडल के सभी अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व को प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग की समीक्षा में लक्ष्य के सापेक्ष सबसे खराब प्रदर्शन जनपद फिरोजाबाद 19 प्रतिशत तथा मैनपुरी 20 प्रतिशत रहे, दोनों जनपदों में,अधिशासी अभियंताओं द्वारा बिल भुगतान कराने में शिथिलता बरतने पर कार्यवाही करने, तथा गलत बिल जेनरेट करने से आ रही समस्या के निराकरण के आदेश दिए। बैठक में नगरीय निकायों में लक्ष्य से कम राजस्व वसूली पर बताया गया कि जनपद आगरा में लक्ष्य के सापेक्ष 23 प्रतिशत, फिरोजाबाद 32, मथुरा 31, मैनपुरी 26 प्रतिशत वसूली की गई, मंडलायुक्त द्वारा कम वसूली पर पूछे जाने पर बताया गया कि आगरा में टैक्सी स्टैंड हटने से राजस्व में कमी आई है, जिसे मंडलायुक्त द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया सभी जनपदों को कार्य योजना बना कर लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए।

बैठक में ताजमहल के आस पास सहित सभी जगह मार्बल, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुओं तथा पेठा के पैकेजिंग पर वार कोड रेट सूची लगाने, मुद्रा एक्सचेंज को डिस्प्ले कराने के निर्देश दिए। बैठक में भूमाफिया तथा भूमि अतिक्रमण की समीक्षा की

गई जिसमें जनपद आगरा में आईजीआरएस पर कुल दर्ज 4013 शिकायतों में लगभग 1000 शिकायत जांच में गलत पाई गईं,2943 सही जिसमें 2908 का निस्तारण किया गया शेष 39 पर कार्यवाही किया जाना बताया गया। मंडलायुक्त द्वारा उक्त निस्तारण शिकायतों पर आपत्ति प्रगट की तथा बताया कि तहसील दिवस में चक रोड पर कब्जा, कूढ़ बंटवारा, पैमाइस न करना, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा जैसी शिकायतों की भरमार है, लेखपालों ने विधिवत शिकायत पंजिका तक नहीं बनाई है, प्राप्त शिकायतों का खराब गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाता है,खनन दैवीय आपदा, डिजिटल क्रॉप सर्वे, घरौंनी इत्यादि की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए।

अब मार्केट से टाटा ईवी की होगी छुट्टी! होंडा ला रही ये पूरी 4 इलेक्ट्रिक कारें, देखें रेंज और फीचर्स

होंडा कंपनी एलिवेट SUV के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को ला रही है। बताया जा रहा है कि इसे मौजूदा एलिवेट के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जाएगा। फुल चार्ज में यह गाड़ी करीब 400 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम होगी।

इंडियन मार्केट का ईवी सेगमेंट इतना बड़ा है। कि यहां पर विदेशी कंपनी अपने इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने की रुचि ले रही है। इस कड़ी में सेडान कारों के लिए मशहू कंपनी होंडा भी टाटा मोटर्स को टक्कर देने के लिए कड़ी तैयारी कर ली है। कंपनी एक के बाद एक चार इलेक्ट्रिक कर को लॉन्च करने वाली है। जिस हाल के फिलहाल फिलहाल के इवेंट में पेश किया था।

कंपनी वर्तमान में 4 नई इलेक्ट्रिक होंडा प्रोलॉग, एलिवेट इलेक्ट्रिक, e:NP2 और e:NS2 जैसी ईवर काम कर रही है, जिन्हें भारतीय बाजार में लॉन्च करने की योजना योजना है

होंडा e:NS2 रेंज 300 किलोमीटर

होंडा गायकिंडो इंडोनेशिया इंटरनेशनल ऑटो शो में अपनी होंडा e:NS2 इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट को पेश किया है, इसे एडवांस तकनीकी फीचर्स के साथ आधुनिक डिजाइन में पेश किया गया है, इसके टोटाइप के केबिन में बड़ी टचस्क्रीन, TFT मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, ओवर द एयर (OTA3) की सुविधा दी गई है। वही ये होंडा e:NS2 ईवी फुल चार्ज में यह गाड़ी करीब 300 किलोमीटर की रेंज देगी है।

होंडा एलिवेट इलेक्ट्रिक रेंज 300 किलोमीटर

होंडा कंपनी एलिवेट SUV के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को ला रही है। बताया जा रहा है कि इसे मौजूदा एलिवेट के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जाएगा। फुल चार्ज में यह गाड़ी करीब 400 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम होगी। इसमें एयरबैग, ADAS तकनीक, हिल असिस्ट और पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स होगें। खबर है कि कंपनी इसे 2025 में देश में लॉन्च करेगी।

होंडा प्रोलॉग रेंज 450 किलोमीटर

कंपनी 2022 में होंडा प्रोलॉग SUV में पेश किया था। कंपनी इसे ऑल-इलेक्ट्रिक कार को "अल्टियम" प्लेटफॉर्म पर बना रही है। इसमें मिलने वाली पावरफुल बैटरी पैक के बदौलत फुल चार्ज करने पर यह 300 से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होगी।

होंडा e:NP2 रेंज 400 किलोमीटर

होंडा भारतीय बाजार के लिए होंडा e:NP2 पर काम कर रही है। इस गाड़ी के प्रोडक्शन मॉडल को अगले साल लॉन्च करेगीयह एक बॉक्सी लुक वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, जिसे सेगमेंट में होंडा एलिवेट इलेक्ट्रिक से ऊपर रखा जाएगा। वही कंपनी इसमें ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करेगी और ये ईवी भी करीब 400 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है।

एक दूसरे से कितनी अलग हैं टाटा नेक्सन ईवी फेसलिफ्ट और ईवी मैक्स, समझ लीजिये

अगर आप टाटा की बेस्ट इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन ईवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन नई और पुरानी के बीच कंफ्यूज हैं. तो हम आगे दोनों की तुलना करने जा रहे हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी।

नई नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट को इतने बड़े अपडेट के साथ, एक बिल्कुल नई कार कहा जा सकता है. हालांकि इसे नेक्सन ईवी मैक्स की नजर से देखना भी जरुरी हो जाता है. ईवी मैक्स हाई रेंज और अपडेटेड पार्ट्स के चलते पहले नेक्सन का सबसे दमदार वेरिएंट था, लेकिन अब नई नेक्सन ईवी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. जिनके बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं.

डिजाइन

नई नेक्सन अपने पहले वाली ईवी मैक्स से थोड़ी ज्यादा लंबी है, जबकि डिजाइन के मामले में पेट्रोल/डीजल नेक्सन की तुलना में नया लुक बिलकुल साफ़ दिखाई देता है. ब्लू एक्सेंट मैक्स के उलट, नई नेक्सन में एक अलग एयरोडायनामिक्स वाला बम्पर और एक रंगीन फॉक्स ग्रिल मौजूद है. साथ ही नेक्सन ईवी मैक्स के उलट ICE नेक्सन और ईवी वन के बीच अंतर साफ है. इसके अलावा पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइटिंग भी दी गयी है, जो एयरो इंसर्ट वाले पहियों के साथ ईवी स्पेसिफिक है. वहीं नई ब्रांडिंग के चलते अब .ev बैज भी मौजूद है.

केबिन

मैक्स को प्रोडक्शन के दौरान कुछ अपडेट मिले हैं, जबकि इसके डार्क वेरिएंट को 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन मिली है. हालाकि, अब टाटा ने स्पष्ट तौर पर नेक्सन ईवी पर फोकस किया है और इसे ICE वेरिएंट से पूरी तरह से अलग कर दिया है. जिसमें अब एक 12.3 इंच की बड़ी टचस्क्रीन है, जो पहले वाली नेक्सन ईवी मैक्स के उलट नई नेक्सन ईवी के लिए खास है. साथ ही इसमें एक समर्पित ऐप सूट भी है, जिससे आप कार को चार्ज करते समय फिल्म देखने के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्सॉन ईवी में अब एक नया टच पैनल और एक नया

गियर सेलेक्टर भी मौजूद है. नई नेक्सॉन ICE की तरह, नई नेक्सॉन ईवी में अब ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा जैसी सुविधाएं भी दी गयी हैं. बेशक, नई नेक्सॉन ईवी में रीजन मोड को स्टीयरिंग पैडल शिफ्टर्स में सेट कर दिया गया है.

रेंज और परफॉर्मेंस

नई नेक्सन ईवी में अब एक नई बैटरी है, जो 20 किलोग्राम हल्की है. साथ ही पिछली नेक्सन ईवी की तुलना में इसमें बेहतर कूलिंग और बेहतर बैटरी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखा गया है. रेंज को और बढ़ाने के लिए ईवी कम रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर भी मौजूद हैं. वहीं पावर की बात करें तो, नई नेक्सन ईवी 145 और 215Nm है, जो मैक्स के 143 bhp और 250 Nm पावर आउटपुट के मुकाबले कम है और रेंज की बात करें तो, इसमें सामान बैटरी पैक के साथ थोड़ा बदलाव के साथ 465 किमी, जबकि मैक्स की रेंज 453 किमी है. बाकी बदलाव में टॉप स्पीड 150 किमी/घंटा के साथ V2V और V2L सुविधा भी मिलती है।

महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार ने कर दिखाया ये बड़ा कारनामा! जानकर उछल पड़ेंगे आप

नई दिल्ली। कार मार्केट में देसी कार मेकर कंपनी महिंद्रा ऐंड महिंद्रा अपने ईवी पोर्टफोलियो को विस्तार करने पर काम कर रही है। जिससे कंपनी लगातार अपनी गाड़ियों को टेस्टिंग में डाल रही है। इस कड़ी में कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का में से एक इलेक्ट्रिक कार का प्रोटोटाइप टेस्ट कर रही है। जिसमें बड़ा कारनामा देखने को मिला है। कंपनी इसे जबरदस्त रेंज में लॉन्च करने वाली है। दरअसल हाल ही में कंपनी ईवी के प्रोटोटाइप की जबरदस्त रफ्तार का टीजर जारी किया है। जिस जो काफी वायरल हो गया है। हाल ही में कंपनी ने चेन्नई में SUV ट्रैक पर BE.05, XUV.e8 और XUV.e9 को 200 किमी/घंटा की रफ्तार में टेस्ट किया है, जिसका दौड़ते हुए एक टीजर भी जारी किया गया है। जो लोगों को काफी पंसद आ रहा है। वही महिंद्रा XUV.e9 प्रोटोटाइप को पहली बार भारत में देखा गया है।

महिंद्रा XUV.e9 को मिलेगा आकर्षक लुक

महिंद्रा अपने खास एसयूवी के लिए जानी जाती है, जिससे लुक और डिजाइन में खास मिलने वाला है, जिससे XUV.e9 के डिजाइन की बात करें तो यह XUV.e8 के मुकाबले में में काफी स्मूथ और आकर्षक दिखती है। वही खबर है कि कंपनी इसे एयरोडायनामिक्स और कूपे प्रोफाइल टेस्ला मॉडल Y से प्रेरित बना रही है। खास बात ये है कि XUV.e9 के नए टीजर में XUV.e8 और BE.05 भी स्पीड के मामले में काफी आकर्षक दिखाती हुई नजर आई हैं। कंपनी ने आने वाली एक EV ने स्पीडोमीटर पर 200 किमी/घंटा को रफ्तार को छू लिया, जो एक ईवी के लिए एक माइस्टोन है।

महिंद्रा ईवी की रेंज लॉन्चिंग EVs

खबर है कि महिंद्रा इन के लिए फॉक्सवैगन से मोटर्स के साथ काम कर रही है, जिससे इन EVs इसकी फ्रंट मोटर सभी वाहनों में 107bhp की पावर और 135Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम होगी। वही कंपनी इन ईवी में से सबसे पहले XUV.e8 दिसंबर में ला रही है, इसके बाद में 2024 के आस-पास XUV.e9 को अप्रैल को लॉन्च करेगी।

फेम-2 स्कीम में गड़बड़ी करने वाली दोपहिया ईवी कंपनियों पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई, सरकार ने चेताया

केंद्र सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिकि ओकिनावा आटोटेक एंपियर ईवी रिवाल्ट मोटर्स बेनिलिंग इंडिया एमो मोबिलिटी और लोहिया आटो को प्रोत्साहन राशि वापस करने को कहा है। अधिकारी के अनुसार कंपनियों को नोटिस भेजा गया है और अब तक केवल रिवाल्ट मोटर्स ने ही रकम वापस करने की पेशकश की है। अंतिम तिथि लगभग निकल चुकी है और अगले सप्ताह सरकार इस संबंध में कुछ फैसला लेगी।

नई दिल्ली। सरकार ऐसी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों के खिलाफ कानूनी विकल्प तलाश कर रही है, जो फेम-2 योजना के नियमों का अनुपालन नहीं कर रही है। केंद्र ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को तेजी से अपनाने और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने से जुड़ी फेम-2 योजना मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर प्रोत्साहन राशि का दावा करने वाली सात इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों से 469 करोड़ रुपये वापस करने को कहा है।

इन कंपनियों पर लगे हैं आरोप

केंद्र सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिकि, ओकिनावा आटोटेक, एंपियर ईवी, रिवाल्ट मोटर्स, बेनिलिंग इंडिया, एमो मोबिलिटी और लोहिया आटो को प्रोत्साहन राशि वापस करने को कहा है। अधिकारी के अनुसार, कंपनियों को नोटिस भेजा गया है और अब तक केवल रिवाल्ट मोटर्स ने ही रकम वापस करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें नोटिस भेजा है। अब तक, केवल रिवाल्ट ने भुगतान करने की पेशकश की है, अन्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

सख्त कदम उठा सकती है सरकार

अंतिम तिथि लगभग निकल चुकी है और अगले सप्ताह सरकार इस संबंध में कुछ फैसला लेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम कानूनी

विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। भारी उद्योग मंत्रालय की जांच से पता चला है कि इन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन कर योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाया है।

योजना के नियमों के अनुसार, भारत में निर्मित कलपुर्जों का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहन की अनुमति दी गई थी, लेकिन जांच में यह पाया गया कि इन सात कंपनियों ने कथित तौर पर आयातित कलपुर्जों का उपयोग किया था।

क्या है मामला?

मंत्रालय ने एक गुमनाम ईमेल प्राप्त करने के बाद जांच की थी। ई-मेल में आरोप लगाया गया था कि कई ईवी निर्माता इन इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध मैन्युफैक्चरिंग योजना (पीएमपी) नियमों का पालन किए बिना सब्सिडी का दावा कर रहे थे।

इसके बाद मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में सब्सिडी वितरण में देरी की। सात इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को मिली अतिरिक्त छूट उनसे ही वापस लेने की संभावना पर विचार करें।

मोदी-शाह की जोड़ी एक साथ कई मुद्दे उछाल कर विपक्ष को कन्फ्यूज कर देती है

डॉ. रमेश ठाकुर

चाहे प्राचीन भारत की बात हो, या आधुनिक समय की, दोनों के परिसंगम में हमारी परंपराओं और घरेलू संस्कृतियों में इंडिया शब्द का कोई वास्ता नहीं? पर, शायद अब भारत के माथे पर जबरन गोदा गया इंडिया नाम सदैव के लिए लुप्त होने की कगार पर है।

'भारत' शब्द हमारी खाटी संस्कृति, देशी रीति-रिवाजों और पुरानी परंपराओं की आत्मा है, तभी उसे भारत माता कहके पुकारते आए हैं। गुजरा वक्त इसी शब्द से गुलजार रहा था। लेकिन जब अंग्रेजों की घुसपैठ हुई, तो उन्होंने अपने मुफादित नया नाम 'इंडिया' गढ़ दिया जिसे भारतीयों को ना चाहते हुए भी अपनाना पड़ा। 200 सालों तक देश उनका बंधक रहा, इस बीच ये नाम भी प्रचलित होता गया। आजादी से लेकर आजतक यानी 275 वर्षों से भारत की जगह इंडिया शब्द ही बोला और लिखा जाता रहा। समूचा संसार भी इंडिया से ही जानता-पहचानता और पुकारता है। ये सच्चाई वैसे हम सभी जानते हैं कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया अंग्रेजों की देन है। क्योंकि इंडिया की उत्पत्ति इंडस यानी सिंधु शब्द से है जो यूनानियों द्वारा चौथी सदी ईसा पूर्व से प्रचलन में रही। इंडिया नाम पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी में और आधुनिक अंग्रेजी में 17वीं सदी से मिलता है।

चाहे प्राचीन भारत की बात हो, या आधुनिक समय की, दोनों के परिसंगम में हमारी परंपराओं और घरेलू संस्कृतियों में इंडिया शब्द का कोई वास्ता नहीं? पर, शायद अब भारत के माथे पर जबरन गोदा गया इंडिया नाम सदैव के लिए लुप्त होने की कगार पर है जिसकी अधिकृत शुरुआत देश की महामहिम द्वारा उस समय हुई, जब उनके कार्यालय से जी-20 कार्यक्रम को लेकर नामचीन हस्तियों को निमंत्रण भेजे गए। निमंत्रण पत्र में उनके पद से 'इंडिया' शब्द हटा हुआ दिखा। अक्सर, भारत के राष्ट्रपति के पद के आगे 'दा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' लिखा होता था। पर, उस स्थान पर 'दा प्रेसिडेंट ऑफ भारत' शब्द दिखाई दिया। जाहिर है इसके बाद सियासी हंगामा कटता और हंगामा कटते हुए देर नहीं लगी? हिंदुस्तान के तकरीबन सभी सियासी दल केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गए हैं। सभी एक सुर में बोलने लगे कि प्रधानमंत्री संविधान से भी छेड़छाड़ करने लगे हैं।

कांग्रेस नेता जयराम की टिप्पणी आई, बोले इंडिया शब्द से आपत्ति क्यों है प्रधानमंत्री को? क्या इसलिए कि जब से विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से अपने संयुक्त गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। जबकि, इससे पूर्व अपने नौ वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने अपनी करीब 150 योजनाओं के नाम इंडिया शब्द से ही रखे। चाहे खेलो इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया? विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने के मूड में है। समूचा विपक्ष विशेष सत्र में इसे मजबूती से उठाएगा। लेकिन, सरकार ने सत्र आने से पहले ही ऐसा धमाका कर दिया जिससे विपक्ष में भगदड़ मच गई। उनमें अभी तक शोर सिर्फ 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर था। लेकिन एक और बड़ा बम फोड़ डाला। मोदी-शाह की जोड़ी एक बात ठीक से जानती है कि एक साथ इतने मसले उठा दो, जिससे विपक्ष कन्फ्यूज हो जाए, कि कौन-सा उठाएं, कौन-सा नहीं?

बहरहाल, 'इंडिया' को 'भारत' कर देना, ये संवैधानिक रूप से सभी सियासी दलों के साथ मंत्रणा करने वाला मुद्दा है। हालांकि अभी भी संदेह के कुछ बादल मंडरा रहे हैं। मात्र राजनीतिक गलियारों में ही चर्चाएं हैं। स्थिति अभी भी साफ नहीं है कि वास्तव में ऐसा होगा, या संविधान से इंडिया शब्द को हमेशा के लिए हटाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बुलाए जा रहे विशेष सत्र में क्या इस मसले पर चर्चा होगी? मसौदा पेश होगा या फिर कोई बिल लाया जाएगा? वैसे, मुद्दा ज्यादा पेचीदा नहीं है कि आसानी से सुलझाया ना जाए? पर, बात वहीं आकर अटक जाती है कि क्या इस बाबत केंद्र सरकार विपक्ष को विश्वास में लेगी, या पूर्व की भांति इस बार भी सबको दरकिनार करके अपने निर्णय पर आगे बढ़ेगी। विपक्षी दल ज्यादातर इसी बात से नाखुश हैं कि सरकार किसी बड़े निर्णय में उन्हें शामिल नहीं करती, अपने मन-मुताबिक फैसले ले लेती है।

भारत-इंडिया की लड़ाई के इतर अगर बात करें, तो केंद्र में मोदी सरकार के बीते साढ़े नौ वर्षों के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला-उल्टा गया। देखा जाए तो कहीं-कहीं जरूरी भी था। मुगल, शाहजहां व अकबर जैसे तमाम पूर्व शासकों के वक्त के इतिहास को बदला गया। उनके द्वारा रखे गए नामों को हटाने का कार्य बीते कई वर्षों से बदस्तूर जारी है। जैसे, पुरानी इमारतें, रेलवे स्टेशनों आदि का नया नामकरण हुआ। इसके अलावा अंग्रेजों के वक्त से चले आ रहे करीब 1500 सौ पुराने कानूनों को खत्म किया है। अंग्रेजों की बनाई संसद को भी स्वदेशी नए भवन में हस्तांतरित कर दिया गया है। इंडिया नाम पड़ने की थ्योरी से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन भारत कैसे पड़ा। इसकी मुकम्मल जानकारियों का बहुत अभाव रहा है। हालांकि, भारत शब्द के पीछे तर्क कोई एक नहीं, बल्कि बहुतेरे हैं। पर, हिंदुओं के महान पौराणिक ग्रंथ 'स्कन्द पुराण' के अध्याय संख्या-37 के मुताबिक ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र का नाम भारत था, जो बड़े बलशाली और शूरवीर थे, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भरत पड़ा। इसका उल्लेख कई जगहों पर मिल जाएगा कि भारतवर्ष का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हुआ। हिंदुस्तान शब्द की भी अपनी एक अद्भुत कहानी है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं की बहुतायत के चलते पड़ा। जबकि, ऐसा है नहीं? हिन्दू और हिन्द दोनों फारसी शब्द हैं जो इंडो-आर्यन संस्कृत सिंधु से आए हैं। आचमेनिड सम्राट डेरियस प्रथम ने लगभग 516 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी पर विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद ये शब्द सिंधु घाटी के लिए इस्तेमाल किया गया।

इंडिया शब्द को हटाने को लेकर सियासत में सुगबुगाहट ही नहीं, बल्कि गर्माहट भी बढ़ गई है। चर्चाएं ऐसी हैं कि हो सकता है बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान से 'इंडिया' शब्द को हटाने कोई बिल आए। प्रस्ताव की तैयारियों की हलचल दिखने भी लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि सदियों से हमारे देश का नाम भारत रहा है? यही रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से बाकायदा अपील की है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल हो। फिलहाल इस मसले को लेकर राजनीति जबरदस्त शुरू हो गई है। पर, ज्यादातर देशवासी इस पक्ष में हैं कि देश को भारत ही बोला जाए। यूरोपीय देशों की भांति अगर इस मसले को लेकर केंद्र सरकार जनमत करवाए, तो परिणाम निश्चित रूप से उनके पक्ष में होंगे। बावजूद इसके मसला भयंकर रूप से पेचीदा है, विपक्ष इतनी आसानी से इंडिया को भारत शायद ही होने दे। आगामी संसद के विशेष सत्र पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसमें क्या वास्तव में इसको लेकर केंद्र सरकार विधेयक लाएगी। अगर लाएगी तो क्या उन्हें सफलता मिलेगी। फिलहाल ये मुद्दा संसद सत्र तक गर्म रहेगा, ये तय है।

संपादक की कलम से

पांच की ही सुरक्षा परिषद

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आकार और 'वीटो' एकाधिकार आज भी वही है, जो करीब आठ दशक पहले था। प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 के मंच से एक बार फिर इसके सुधारों और विस्तार का मुद्दा उठाया था। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सरीखे विश्व-नेताओं ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। पैरवी और आग्रह भी किए गए हैं। यह समर्थन बीते कुछ वर्षों के दौरान निरंतर रहा है, लेकिन चीन भारत की सदस्यता के खिलाफ आक्रामक रहा है। चीन भूलता रहा है कि वह सुरक्षा परिषद में 'वीटो' अधिकार वाला स्थायी सदस्य है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की 'कृपा' अथवा ऐतिहासिक गलती के कारण है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस भी जी-20 सम्मेलन के दौरान उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने बदलती विश्व-व्यवस्था के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में सुधारों और विस्तार की बात नहीं की। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, ताकि देशों के बीच आपसी शांति, स्थिरता और सह-अस्तित्व का स्थायी भाव बरकरार रहे और युद्ध को नेपथ्य में धकेला जा सके। तब से लेकर आज तक कमोबेश सुरक्षा परिषद के पांच वीटोधारी देशों-अमरीका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन-में न तो कोई सुधार किया गया है और न ही यह संख्या बढ़ाई जा सकी है। अलबत्ता 1965 में इतना विस्तार जरूर किया गया कि गैर-स्थायी सदस्यों की संख्या 10 कर दी गई। वे बारी-बारी से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनाए जा सकते हैं।

भारत भी इन देशों में शामिल है। रूस को सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी जगह स्थायी सदस्यता, वीटो समेत, दी गई। बहरहाल स्थायी सदस्य अपने 'वीटो' का दुरुपयोग भी करते रहे हैं। भारत के संदर्भ में चीन 'अड़ंगेबाज' बना रहा है, क्योंकि वह अमरीका और भारत के आतंकवाद-विरोधी प्रस्तावों पर 'वीटो' कर मसूद अजहर सरीखे खूंखार आतंकियों और इनसानियत के कातिलों को बचाता रहा है। इस तरह चीन अपने 'कर्जदार दोस्त' पाकिस्तान की किरकिरी से उसे बचाता रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में सुधारों को पारित करना ही टेढ़ी खीर है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए दो-तिहाई सदस्य-देश संशोधन के पक्ष में वोट करें। अनिवार्य यह है कि इस प्रक्रिया में सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी, वीटोधारी सदस्यों की उपस्थिति भी जरूरी है। उनके बिना कोई भी संशोधन और प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में पारित नहीं किया जा सकता। बीते कुछ सालों में सुधारों के पैरोकार देशों की मांग बुलंद हुई है। इस समूह में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। समूह को 'जी-4' का नाम दिया गया है।

जापान, जर्मनी, भारत तो विश्व की सबसे बड़ी तीसरी, चौथी और 5वीं अर्थव्यवस्थाएं हैं। उनकी स्थायी भागीदारी को सुरक्षा परिषद में कैसे रोका जाता रहा है? आम सहमति के लिए इन देशों के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी देशों-पाकिस्तान, इटली, अर्जेन्टीना और दक्षिण कोरिया और अफ्रीकी संघ-की आवाज भी मिलाई गई है। हालांकि जी-4 के देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पक्षधर हैं, जबकि आम सहमति के लिए जुड़े देश चाहते हैं कि गैर-स्थायी सदस्यों की सीटें बढ़ाई जाएं। अफ्रीकी संघ चाहता है कि दो अफ्रीकी सीटें स्थायी रखी जाएं और उन्हें 'वीटो' अधिकार भी दिया जाए। चीन समूचा खेल बिगाड़ता रहा है, क्योंकि वह पाकिस्तान, इटली वाले 'आम सहमति के लिए जुड़े' देशों के साथ है। चीन भारत और जापान को स्थायी सदस्य बनाए जाने के खिलाफ है। बहरहाल सुरक्षा परिषद को मौजूदा हालात और विश्व-व्यवस्था में प्रासंगिक बने रहना है, तो सुधारों और विस्तार की पहल करनी ही पड़ेगी। इस मसले पर गुटबाजी नहीं होनी चाहिए।

राय

मंडे का एक्शन

हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठकों से कहीं आगे निकलती हुई सरकार की मंडे मीटिंग अपनी हैसियत के साथ ऐलान और रणनीति जोड़ रही है, तो इस पद्धति के गुणात्मक असर को यह प्रदेश सफल होते देखना चाहता है। मंत्रिमंडल में सुक्खू सरकार होती है, तो मंडे मीटिंग मुख्यमंत्री का नित नया अवतार पेश करती है। जुगत बैठाने के लिए एक सशक्त निर्णायक मंच चाहिए और इस तरह हम देख सकते हैं कि 'मंडे का एक्शन' अपनी निरंतरता के साथ प्रदेश की अपेक्षाओं, जरूरतों और चुनौतियों पर हर हफ्ते एक नई कहानी लिख रहा है। आपदा के इस दौर में केंद्र को कठघरे में खड़ा करने की जुर्रत यह पहाड़ी राज्य कर रहा है, तो आंतरिक मामलों के दलदल में फंसे आर्थिक रथ व विपक्षी प्रतिकूलता के सम्मुख नई परिभाषाएं जोड़ रहा है। यह मुख्यमंत्री का एक्शन माना जाएगा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुछ ड्रीम प्रोजेक्टों को ठंडे बस्ते में डालकर, उन्हें मंडी की परिधि तक ही बयान देने को उकसा रहे हैं। मंडी की शिवधाम, विश्वविद्यालय व प्रस्तावित एयरपोर्ट आदि परियोजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री की सियासी कसौटी पर मापी जाती हैं। जाहिर तौर पर शिवधाम परियोजना ऐसे चरण में फंसी है, जहां भाजपा के लिए मुद्दा और जयराम ठाकुर के लिए एक सपना रुका हुआ है। इसी तरह विवादित सियासी पट्टी पर आकर मंडी एयरपोर्ट का ख्वाब रेखांकित करके भी पूर्व मुख्यमंत्री यह तो नहीं कह सकते कि वर्तमान मुख्यमंत्री कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए दो हजार करोड़ क्यों जाया कर रहे हैं। मंडी विश्वविद्यालय के पर काटकर वर्तमान सरकार ने प्रश्नों की फांस में क्षेत्रवाद को फंसा दिया है। इसके अस्तित्व में पूर्व मुख्यमंत्री की वकालत को हल्के से नहीं लिया जा सकता, फिर भी वह एक सीमित परिधि में इन तीन परियोजनाओं की मिलकीयत में सियासत की धुरी तो बनेंगे ही। बहरहाल, हिमाचल की वर्तमान राजनीति में कांग्रेस की सत्ता को पढने के लिए 'मंडे मीटिंग' सबका ध्यान आकृष्ट कर रही है। यह एक पैकेज की तरह उस जनमंच को खरीद चुकी है, जो पिछली सरकार के आमंत्रण में जनसंवेदना को ढोता रहा है। मंडे मीटिंग दरअसल मुख्यमंत्री के प्रभुत्व का मनोविज्ञान तथा सरकार के एकछत्र साम्राज्य का प्रादुर्भाव है। यहां फाइलें लटकती नहीं और न ही विभिन्न समीक्षाओं की देहरियों पर घूमती हैं, बल्कि एक साप्ताहिक ऐलान की तरह सरकार अपने एक्शन मोड का संचालन कर रही है। इसी हफ्ते की सबसे बड़ी सुर्खी मंडे मीटिंग से ऐलान कर रही है कि आपदा प्रभावित करीब 13 हजार परिवारों को सरकार किराये के मकानों में ठहराएगी। यह एक बड़ा एक्शन ही नहीं, बल्कि सरकारी कामकाज की परिपाटी को बदलने की मंशा है। अगर यही फैसला वाया मंत्रिमंडल आता, तो चर्चाओं के कई मंच व अनुमतियों के द्वार खुल जाते, लेकिन 'मंडे मीटिंग' हिदायत के पिटारे से एक त्वरित कार्रवाई का आदेश कर रही है। अंततः ऐसे फैसले जिला स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी को भी सक्रिय करते हुए लक्ष्य सौंप रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आपदा प्रभावितों के लिए छत ढूंढने की नई परंपरा जब सामने आएगी, तो राहत की भूमिका भी बदलेगी और एक स्थायी समाधान भी होगा। ऐसे में मंडे मीटिंग एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन के परचम को तीव्रता से फहराने का जरिया हो सकता है। वीभत्स मंजर और अपनी यादों के आशियाने से दूर हुए आपदा प्रभावित अगर अगली कार्रवाई व पुनर्वास तक, रहने के लिए ठौर हासिल करते हैं, तो आंसुओं को थामने का एक नजरिया भी सामने आ जाएगा। प्रदेश और समाज के बीच कुछ भूमिकाएं बांटी जा सकती हैं। समाज ऐसे फैसलों का लाभान्वित पक्ष व समर्थक बन जाएगा।

नया आर्थिक गलियारा सिर्फ चीन को सबक नहीं सिखायेगा बल्कि दुनिया का भला भी करेगा

डॉ. आशीष वशिष्ठ

भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पश्चिम में भारत की जमीनी कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा और पाकिस्तान की रोक को बेअसर करेगा। साल 1990 में ही पाकिस्तान ने भारत की जमीनी कनेक्टिविटी के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देने से मना कर दिया था।

जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि कूटनीति और कारोबार की दुनिया में आने वाला समय भारत का है और चीन के लिए आगे की राह अब आसान नहीं होने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का विकल्प होगा। यह कॉरिडोर 6 हजार किमी लंबा होगा। इसमें 3500 किमी समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40 प्रतिशत समय की बचत होगी।

इस कॉरिडोर का नाम इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस प्रोजेक्ट में भारत, यू.ए.ई, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल होंगे। इस गलियारे की स्थापना सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि इसके निर्माण के साथ ही दुनिया के व्यापार का भूगोल बदल जाएगा। प्रस्तावित गलियारा भारत से संयुक्त अरब अमीरात तक अरब सागर में फैला होगा, फिर यूरोप से जुड़ने से पहले सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल पार करेगा।

इस परियोजना के तहत समुद्र के नीचे केबल और ऊर्जा परिवहन बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक सांझेदारी बताते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग का एक बड़ा माध्यम होगा। इस कोरिडोर से दुनिया की कनेक्टीविटी को एक नई दिशा मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गलियारे में शामिल देशों के लिए यह परियोजना अनंत अवसर प्रदान करेगी। इससे व्यापार करना तथा स्वच्छ ऊर्जा निर्यात करना आसान बन जाएगा। यह किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं है।

भारत-मिडल ईस्ट-यूरोप शिपिंग और रेलवे कनैक्टिविटी कोरिडोर की योजना को एक बड़ी बात करार देते हुए अमरीकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगले दशक में भागीदार देश निम्न-मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करेंगे। इस योजना में शामिल सभी 9 देशों के प्रमुखों तथा प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहते हुए बाइडेन ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य यही इस जी-20 शिखर सम्मेलन का फोकस है। क्षेत्र में चीन के आर्थिक दबदबे को चुनौती देते हुए अमरीका और यूरोपीय संघ ने भारत को मध्य पूर्व और भू-मध्य सागर से

जोडने वाले एक नए जहाज और रेल गलियारे के विकास का समर्थन किया है। निश्चित तौर पर इस प्रोजेक्ट को महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच एक ग्रीन और डिजिटल पुल माना जा रहा है।

ऐसे में अहम प्रश्न यह है कि इस गलियारे से भारत को क्या लाभ होगा। जानकारों के अनुसार भारत को पहला लाभ यह होगा कि मिडल ईस्ट और यूरोप के बाजारों में भारत की पहुंच और पकड़ मजबूत हो सकती है। दूसरा लाभ होगा कि शिप और रेल कनेक्टिविटी होने से कम से कम लागत में तेल और गैस की सप्लाई होगी। तीसरा लाभ यह होगा कि मिडल ईस्ट और यूरोप में चीन पर भारत को कूटनीतिक और कारोबारी बढ़त मिलेगी। अब सवाल ये है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट में बढ़-चढ़कर क्यों हिस्सा ले रहा है। इसकी वजह चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए ड्रैगन मिडल ईस्ट से यूरोप के बाजारों पर कब्जा जमाना चाहता है। अमेरिका की कोशिश चीन के प्रभाव को रोकने की है, इसलिए उसने भारत की मदद ली और सऊदी अरब-यूएई को नए कॉरिडोर के लिए तैयार किया। इसकी घोषणा से पहले अमेरिकी अधिकारी फाइनर ने कहा था कि अमेरिका की नजर में ये समझौता पूरे क्षेत्र में तनाव कम करेगा और हमें ऐसा लगता है कि इससे टकराव से निपटने में मदद मिलेगी।

इस कॉरिडोर की अगुवाई भारत और अमेरिका साथ मिलकर करेंगे। इस समझौते के तहत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम होगा। यह ट्रेड रूट भारत को यूरोप से जोड़ते हुए पश्चिम एशिया से होकर गुजरेगा। भारत और अमेरिका के अलावा पश्चिम एशिया से संयुक्त अरब अमीरात व सऊदी अरब और यूरोप से यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली व जर्मनी भी इसका हिस्सा होंगे।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने परियोजना के शुभारंभ पर कहा, ''यह महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच एक हरित और डिजिटल सेतु है।'' रेल से भारत और यूरोप के बीच व्यापार 40 प्रतिशत तेज हो जाएगा। भारत मिडल ईस्ट-यूरोप आर्थिक गलियारे का उद्देश्य मध्य पूर्व के देशों को रेलवे से जोड़ना और उन्हें बंदरगाह के माध्यम से भारत से जोड़ना है जिससे शिपिंग समय, लागत और ईंधन के इस्तेमाल में कटौती करके खाड़ी से यूरोप तक ऊर्जा और ट्रेड में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में 2 अलग-अलग कोरिडोर शामिल होंगे। जहां एक ओर पूर्वी कोरिडोर भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा वहीं उत्तरी कोरिडोर खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ेगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशेएटिव यानी बी.आर.आई. प्रोजेक्ट की तर्ज पर ही इसे एक महत्वाकांक्षी योजना माना जा रहा है। महत्वाकांक्षी आर्थिक गलियारे की घोषणा को इस्राइल के लिए 'बड़ी खबर' बताते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि 'हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सहयोग परियोजना' पश्चिम एशिया का चेहरा बदल देगी। यह इजराइल और पूरी दुनिया को लाभान्वित करेगा।

जहां तक भारत का सवाल है तो ये क्षेत्रीय सीमाओं को नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ-साथ कनेक्टिविटी भारत की मुख्य प्राथमिकता है। कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार नहीं बल्कि आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। आज जब हम कनेक्टिविटी की इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण समय पर हुआ है क्योंकि जी-20 साझेदारी में शामिल विकासशील देशों के लिए वाशिंगटन को एक वैकल्पिक साझेदार और निवेशक के रूप में पेश किया जा रहा है।

काले कछुए की सकुशल वापसी

गांव के सूखे पोखर में गांव के बच्चे तैर रहे थे कि अचानक उनको काले रंग का कछुआ दिखा। काले रंग के कछुए को देखकर वे चिल्लाए, 'काला कछुआ! काला कछुआ!' उनकी आवाज सुन सूखे की मार झेलते खेत में काम करता गोबर दौड़ा दौड़ा आया। उसने देखा, सच्ची को काला कछुआ गांव में आया है। कछुआ हौलदार, पटवारी से भी धीमे चल रहा था। जरूर उनसे भी खास पद का होगा। अब किस विभाग का होगा? गोबर तय नहीं कर पा रहा था। क्योंकि इनके सिवाय दूसरे विभागों के कछुओं से उसका वास्ता न पड़ा था। गोबर ने काले कछुए को प्रणाम कर उसे अपनी गोद में उठाया और गांव में ले आया। जिसने भी काले कछुए को देखा वह दंग रह गया। आखिर होरी ने सरकारी नौकर भक्ति का परिचय देते गोबर से कहा, 'रे गोबर! चल इसे वन विभाग को सौंप दें। यह वनचर है।' 'पर बाबा, यह वनचर नहीं, जलचर है।

कायदे से इसे मछली विभाग को देना चाहिए।' 'नहीं, आजकल आदमी को छोडक़र मगरमच्छ, कछुए, गैंडे, दरियाई घोड़े, पंछी सब वनचरों के अंडर ही आते हैं।' आखिर मोबाइल से वनचर विभाग से संपर्क साधा गया। चार दिन बाद कछुए की चाल चलती वनचर विभाग की टीम गोबर के गांव पहुंची। 'कहां है हमारी जात का कछुआ? इसे कौन यहां पर बहला फुसला कर लाया? जो भी इसे यहां बहला फुसला कर लाया हो वह इसी वक्त अपना जुर्म कबूल करे, वर्ना'।' वनचर हेड ने गीदड़ की तरह गुर्राते कहा। 'आकप कसम जनाब! कोई नहीं। जनाब! गांव के लोगों के बहला फुसला कर लाने से आज तक गांव में सरकारी सांप तक नहीं आया तो ये तो कछुआ है जनाब! आ गया हो होगा सरकारी कालोनी के गंदे हवा-पानी से तंग आकर यहां हवा-पानी बदलने', कह होरी ने विनम्र निवेदन करते कहा और उस ओर इशारा किया जहां काले रंग का कछुआ खा पीकर

आराम फरमा रहा था। 'आखिर खरगोशों के गांव में यह काला कछुआ आया कहां से? पर्सनल असिस्टेंट! सभी विभागों को फोन लगाकर पता कराओ कि किसके विभाग से कछुआ अबसेंट है?' 'जी साहबजी! पर साहबजी! जहां तक मेरी नॉलिज है, इस रंग का कछुआ मैंने आज तक किसी भी विभाग में नहीं देखा।' 'तो इसका मतलब है कि'।' 'जनाब! कछुआपन माफ! तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह कछुआ कहीं और से किसी सरकारी विभाग में नया नया ट्रांसफर होकर आया होगा। तभी इसका रंग हमारे रंग से अलग है।

हमारे यहां के किसी भी विभाग का होता तो हमसा रंगदार दिखता। हो सकता है यहां नया नया होने पर अपने दफ्तर जाते जाते दफ्तर का रास्ता भूल गया हो और'।' 'उठाओ अपनी जात बिरादरी के को! इसका रंग काला हुआ तो क्या हुआ? मन दिमाग तो हमारे जैसा है। रंग भेद है तो क्या हुआ! है तो अपना ही बिरादर न! सरकारी कछुए भाई भाई!' आगे कुछ कहने के बदले वनचर टीम ने काला कछुआ अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने रास्ते हो लिए तो गांव ने चैन की सांस ली। पहली बार अबके गांव में सरकारी टीम के लिए खाने पीने का प्रोग्राम नहीं हुआ था। यह देख होरी भी परेशान था। सारे रास्ते में वनचरिए काले रंग के कछुए को गाड़ी में सबसे आगे बिठाए इस बात पर मंथन करते रहे कि आखिर हमारा भाई गांव में गया तो क्यों? गांव जाने से तो बड़े से बड़ा बीमार से बीमार अफसर डरता है। उसका वहां तबादला हो जाए तो वह बीमार से बीमारतम्हो जाता है। फिर अनुमान लगाया गया, हो सकता है, बाहर के राज्य का कोई गुंडा हमारे कछुए भाई को अगुआ कर इस गंदे गांव के आसपास छोड़ गया हो। बाद में कछुआ भाई मुफ्त का खिलाने पिलाने वालों को ढूंढता ढूंढता गांव पहुंच गया हो। एक सुखद सूचना! आज के अखबार से पता चला है कि काले कछुए से पूछकर उसे उसके विभाग में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। परंतु इस अप्रत्याशित घटना के बाद हर विभाग ने अपने अपने रंग बिरंगे कछुओं को खास हिदायत जारी कर दी है कि बिना अपने बॉस को बताए कोई भी कछुआ कहीं न जाए। जाएगा तो वह अपनी सुरक्षा का खुद जिम्मेदार होगा। जनता अब लामबंद हो रही है।

अशोक गौतम

2016 से अब तक कितना बदला यूपीआई?

कई नए फीचर्स हुए एड, कैसा रहेगा भविष्य

यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान में एक क्रांति साबित हुआ है। लोग डिजिटल पेमेंट से जितना डरते थे अब उतना ही भरोसा करते हैं। यूपीआई पर लोगों का भरोसा हर साल बढ़ता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर UPI में अब तक ऐसे कितने बदलाव किए गए हैं जो लोगों को बेहतर पेमेंट का अनुभव प्रदान कर रहे हैं।

नई दिल्ली। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) एक ऐसी टेकनीलॉजी है जिसने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियां बटोरी है। भारत ने यूपीआई डिजिटल पेमेंट में एक क्रांति साबित हुआ है। लोग जितना पहले डिजिटल पेमेंट से डरते थे, अब वो उतने ही इसपर भरोसा करने लगे हैं।

तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि साल दर साल लोगों का भरोसा यूपीआई पर इतना बढ़ गया। आखिर अब तक यूपीआई में ऐसे कितने बदलाव हुए या यूं कहें कि यूपीआई में अब तक ऐसे कितने फीचर जोड़े गए जिसने लोगों का ऑनलाइन पेमेंट करने का अनुभव बेहतर बनाया है। चलिए जानते हैं क्या है यूपीआई की अब तक की यात्रा।

कब शुरू हुआ था यूपीआई?

यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था। 2016 का विमुद्रीकरण, भारत के डिजिटल भुगतान के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ। 500 और 1000 रुपये के नोट चलन से बाहर होने के छह महीने से भी कम समय में, यूपीआई पर कुल ट्रांजैक्शन की मात्रा 2.9 मिलियन से बढ़कर 72 मिलियन हो गई।

2017 के अंत तक, यूपीआई लेनदेन पिछले वर्ष की तुलना में 900 प्रतिशत बढ़ गया था। इसके अलावा साल 2016 में ही जियो के लॉन्च होने के बाद देश में डाटा सस्ता मिलने लगा जिसे यूपीआई पेमेंट को और बढ़ावा दिया।

कितने देशों में चलता है यूपीआई?

यूपीआई देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। यही कारण है कि इसकी सफलता के 7 साल में ही 10 देशों ने यूपीआई को अपना लिया है। ये देश सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यूके है। इन देशों में रहने वाले एनआरआई पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं।

अब तक कितना अपडेट हुआ यूपीआई?

किसी तकनीक की डिमांड तब तक रहती है जब तक उसमें अपडेट आते रहते हैं जिससे लोगों को फायदा होता है। वैसे तो साल 2023 तक यूपीआई के फीचर्स में काफी बदलाव देखने को मिला है। चलिए जानते हैं कि अपने लॉन्च से अब तक यूपीआई कितना बदला है।

2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई ग्राहकों को कैश रखने की झंझट से आजादी दिलाते हुए उनके बैंक अकाउंट से जुड़कर आसानी से ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है।

यूपीआई के सबसे बड़े फीचर्स में से एक यह है कि NCPI ने UPI पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं रखा है यानी सारा ट्रांजैक्शन फ्री है।

फोन नंबर के अलावा आप यूपीआई के माध्यम से QR कोड को स्कैन कर भी पेमेंट भेज सकते हैं।

हाल ही में जुड़े नए फीचर्स:

आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपीआई में एनपीसीआई ने चार नए फीचर्स को जोड़ा है। चलिए एक-एक कर समझते हैं।

UPI पर क्रेडिट लाइन की सुविधा:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अब यूजर्स को लेनदेन करने के लिए बैंकों द्वारा जारी पूर्व-अनुमोदित क्रेडिट लाइनों की सुविधा देगा।

क्रेडिट लाइन एक लचीला लोन है जो कुछ बैंक पेश करते हैं। यह एक पूर्व-अनुमोदित, निर्धारित धनराशि के रूप में काम करता है जिसे आप जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं।

एनपीसीआई ने बताया कि, 'क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई' के फीचर के जरिए क्रेडिट लाइन का लाभ उठाने, कनेक्ट करने और उपयोग करने की प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी।

यूपीआई लाइट एक्स:

एनपीसीआई ने अभी हाल ही में ऑफलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई लाइट एक्स (UPI Lite X) को लॉन्च किया है, जो यूजर्स को पूरी तरह से ऑफलाइन रहते हुए पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह सुविधा ग्राहकों को फ्लाइट, अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशनों और अन्य व्यापारिक स्थानों के लिए भी उपयोग के मामले में काफी काम आएगा जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता।

यूपीआई टैप एंड पे:

एनपीसीआई ने यूपीआई टैप एंड पे (UPI Tap & Pay) भी लॉन्च किया, जो यूजर्स को नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी)-आधारित भुगतान करने की अनुमति देता है।

हेलो यूपीआई:

एनपीसीआई ने इसके अलावा हेलो यूपीआई ('Hello! UPI') की भी सुविधा को भी लॉन्च किया है। हेलो यूपीआई पर संवादात्मक भुगतान के लिए यूपीआई सुविधा यूपीआई अनुप्रयोगों, टेलीफोन कॉल और आईओटी उपकरणों के माध्यम से आवाज-सक्षम भुगतान की सुविधा देती है।

अगस्त में यूपीआई से हुआ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन

एनपीसीआई के अनुसार, वर्तमान में, यूपीआई का उपयोग 350 मिलियन लोग करते हैं। पिछले महीने यानी अगस्त में यूपीआई ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार 10 बिलियन (या 1,000 करोड़) लेनदेन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया था। आपको बता दें कि अगस्त में 15.76 लाख करोड़ रुपये के यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए थे।

ग्लोबलडेटा रिसर्च के अनुसार, नकद लेनदेन 2017 में कुल मात्रा के 90 प्रतिशत से घटकर 2021 में 60 प्रतिशत से भी कम हो गया है।

कैसा होगा यूपीआई का भविष्य?

यूपीआई की भविष्य की अगर बात करें तो यूपीआई का भविष्य काफी उज्ज्वल है। यूपीआई, जिसमें भारत का 75 प्रतिशत डिजिटल लेनदेन शामिल है, के 2026 तक चार गुना बढ़ने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले पांच वर्षों में खुदरा डिजिटल भुगतान में यूपीआई के ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार के कारण कुल लेनदेन मात्रा का लगभग 90 प्रतिशत हो सकता है।

स्टील सेक्टर में ग्रोथ को लेकर आईसीआरए ने बदला अपना अनुमान, संशोधित कर किया 10 प्रतिशत

घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने उच्च सरकारी पूंजीगत व्यय के कारण इस वित्तीय वर्ष में घरेलू इस्पात उद्योग की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को आज संशोधित कर 9-10 प्रतिशत कर दिया। ICRA ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत में इस सेक्टर में स्टील इंडस्ट्री की ग्रोथ करीब 7-8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था।

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी इक्रा (Icra) ने मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय के कारण आज घरेलू इस्पात उद्योग (Steel Industry) के लिए इस वित्तीय वर्ष में अपने विकास अनुमान को संशोधित कर 9-10 प्रतिशत कर दिया। आपको बता दें कि इक्रा ने पहले चालू वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत में उद्योग में स्टील की वृद्धि 7-8 प्रतिशत के दायरे में होने का अनुमान लगाया था।

इस वजह से बढ़ रही है डिमांड

इक्रा ने बताया कि सरकार के बुनियादी ढांचे में विकास मॉडल के कारण घरेलू इस्पात की मांग वित्त वर्ष 2022 से दोहरे अंकों में बढ़ रही है, और यह गति चालू वित्त वर्ष में भी जारी है। इस वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के बीच में अब तक स्टील की मांग में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई को इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कॉरपोरेट सेक्टर रेटिंग्स के समूह प्रमुख जयंत रॉय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में लगभग 14.3 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) नई इस्पात निर्माण क्षमता चालू होने की उम्मीद है। यह हाल के दिनों में किसी एक वर्ष में उद्योग द्वारा किया गया सबसे बड़ा क्षमता विस्तार होगा। वित्त वर्ष 2025 में भी उद्योग की आपूर्ति पाइपलाइन मजबूत रहने की उम्मीद है, जब अनुमानित 12.3 एमटीपीए क्षमताएं कमीशनिंग के लिए तैयार होंगी।

घरेलू मोर्चे पर परिचालन माहौल सहायक

इक्रा ने कहा कि घरेलू मोर्चे पर परिचालन माहौल सहायक बना हुआ है, लेकिन उद्योग को बाहरी माहौल में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें चीनी आवास बाजार का मंदी, देश की इस्पात मांग को चलाने वाला एक प्रमुख इंजन और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में निम्न आर्थिक विकास की संभावनाएं शामिल हैं।

इनसाइड

लोन लेने वालों को आरबीआई ने दी राहत, समय पर बैंकों ने नहीं लौटाए प्रॉपर्टी के दस्तावेज तो देना होगा जुर्माना

आरबीआई की ओर से कहा गया कि लोन पूरा होने के 30 दिन के अंदर ही ग्राहकों को दस्तावेजों वापस करने होंगे। अगर कोई बैंक ऐसा करने में विफल हो जाता है तो उसे ग्राहकों को 5000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बुधवार को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कहा गया कि अगर ग्राहक द्वारा लोन का भुगतान कर दिया गया है, तो उससे जुड़े पेपर्स बैंकों और वित्तयी संस्थाओं को लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर लौटाने होंगे।

नियम का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर लगेगा जुर्माना

आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि अगर कोई बैंक और वित्तीय संस्था इस नियम का पालन नहीं करती है तो उसे ग्राहक को 5000 रुपये प्रति दिन की देरी के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

कई वित्तीय संस्थाएं करती थीं देरी

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि आरबीआई की ओर से नोट किया कि कई वित्तीय संस्थाओं की ओर से गिरवी रखी गई संपत्तियों के दस्तावजों को लोन पूरा होने के बाद रिलीज करने में देरी की जाती थी। ये ग्राहकों से झगड़े का कारण भी बनता था।

लोन जारी करते समय ही लिखा होगा दस्तावेज लौटाने का स्थान

आरबीआई की ओर से कहा गया कि अगर प्रॉपर्टी के दस्तावेज लोन जमा होने के 30 दिनों के अंदर वापस नहीं किए जाते हैं तो इसमें देरी होने के कारण को बैंक और वित्तीय संस्था को ग्राहकों को बताना होगा। साथ ही कहा गया कि लोन जारी करने के लेटर में ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज वापस करने की टाइमलाइन और जगह के बारे में बताना होगा।

दस्तावेज खोने पर ग्राहकों की करनी होगी मदद

अगर किसी कारण से ग्राहकों की ओर से लोन के लिए गिरवी रखे गए दस्तावेजों को बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा खो दिया जाता है, तो दोबारा से पाने के लिए ग्राहकों को मदद करनी होगी। साथ ही इसमें आने वाले खर्च को भी उठाना होगा। हालांकि, ऐसे मामले में वित्तीय संस्थाओं को 30 दिनों को अतिरिक्त टाइम (कुल 60 दिन) मिलेंगे और इसके बाद ही पेनल्टी कैलकुलेट की जाएगी।

बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड बेच कर जुटाए 2000 करोड़, करीब 6 फीसदी उछले शेयर, जानिए कहां होगा इन पैसों का इस्तेमाल

देश के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि उसने 7.88 प्रतिशत की कूपन रेट पर टियर- II बांड के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बैंक ने कहा कि यह राशि एनएसई के ई-टेंडरिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुटाई गई थी। आज बाजार बंद होने तक बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 6 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला।

नई दिल्ली। देश की बड़ी सरकारी बैंक में से एक बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने आज बताया कि उसने 7.88 प्रतिशत की कूपन दर पर टियर II बांड के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

पेशकश से अधिक मिला रिस्पॉन्स

बैंक ने बताया कि यह राशि एनएसई के इलेक्ट्रॉनिक बोली मंच पर जुटाई गई थी। बैंक ने कहा कि उसे 2,000 करोड़ रुपये की पेशकश के मुकाबले 3,770 करोड़ रुपये की 83 बोलियां प्राप्त हुईं।

बैंक कहां करेगी इन पैसों का इस्तेमाल?

बैंक ने बताया कि इन पैसों का उपयोग बैंक की समग्र पूंजी को बढ़ाने और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लॉन्ग टर्म संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। बैंक ने कहा कि इस राशि का उपयोग किसी विशेष परियोजना के वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाएगा।

आज करीब 6 प्रतिशत उछले बैंक के शेयर

आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आज एनएसई पर 5.90 रुपये यानी 5.99 प्रतिशत बढ़कर 104.35 रुपये हो गया। वहीं अगर कुल बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज 398 अंक चढ़कर 45,909 पर बंद हुआ।

पहले तिमाही में हुआ था मुनाफा

पहली यानी चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के नतीजे के मुताबिक बीओआई का नेट प्रॉफिट लगभग तीन गुना बढ़कर 1,551 करोड़ रुपये हो गया था। बैंक ने इसका कारण बैड लोन (एनपीए) में गिरावट को बताया था।

नतीजे जारी करते हुए बैंक ने बताया था कि पिछले साल की समान अवधि में उसे 561 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट जेनरेट हुआ था।

बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल आय बढ़कर 15,821 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 11,124 करोड़ रुपये थी।

एनसीएलटी ने कॉफी डे ग्लोबल के खिलाफ दिवालिया आदेश को किया रद्द

कंपनी का इंडसइंड बैंक के साथ हुआ समझौता

कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड और इंडसइंड बैंक की ओर से आए वकील ने बुधवार को एनटीएलएटी की चेन्नई पीठ को कंपनी और बैंक बीच हुए समझौते के बारे में बताया। इस कारण एनसीएलएटी ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया आदेश को रद्द कर दिया है। कॉफी डे ग्लोबल देश कैफे कॉफी डे नाम से कैफे की चेन चलाती है।

नई दिल्ली। कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड (CDGL) और इंडसइंड बैंक के बीच में बकाया लोन राशि को लेकर समझौता हो गया है। इस कारण NCLAT ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया आदेश को रद्द कर दिया है। कॉफी डे ग्लोबल देश में कैफे कॉफी डे नाम से एक कॉफी चेन चलाती है।

कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड और इंडसइंड बैंक की ओर से आए वकील ने बुधवार को एनटीएलएटी की चेन्नई पीठ को कंपनी और बैंक बीच हुए समझौते के बारे में बताया। साथ ही दिवालिया मुकदमा वापस लेने की अपील की।

दिवालिया आदेश किया रद्द

वकील की ओर से दी गई दलील को न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल और श्रीशा मेरला की दो सदस्यीय पीठ ने सुना और दलील पूरी होने के बाद कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड को दिवालिया घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया।

इससे पहले एनसीएलएटी की ओर से एनसीएलटी के एक आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें सीडीजीएल के खिलाफ दिवालिय प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था।

बता दें, 20 जुलाई को बेंगलुरु की एनसीएलटी बेंच में इंडसइंड बैंक ने एक अर्जी दी थी, जिसमें 94 करोड़ रुपये की बकाया राशि को क्लेम किया गया था।

कॉफी कैफे डे (Coffee Cafe Day) का कारोबार

कॉफी कैफे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) देश के 154 शहरों में 469 कैफे और 268 सीसीडी वैल्यू एक्सप्रेस कियोस्क चलाती है। इसके साथ ही कंपनी होटल, वर्कप्लेस पर 48,788 वेंडिंग मशीन ऑपरेट करती है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी की आय 869 करोड़ रुपये रही थी। इस दौरान कंपनी ने 67.77 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया था।

गोल्ड और सिल्वर की कीमतों ने लगाया गोता, 1000 रुपये टूटा चांदी का भाव

- 1000 रुपये सस्ती हुई चांदी।
- दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,600 रुपये है।
- लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,600 रुपये है।

बुधवार 13 सितंबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में अगर आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज इन्हें कम कीमत पर खरीदने का अच्छा मौका है। जानिए आज सोने-चांदी की कीमत में कितनी गिरावट आई है और आपके शहर में 10 ग्राम सोने की क्या कीमत है।

नई दिल्ली। बुधवार 13 सितंबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप सोना और चांदी की खरीदी करने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे में आज इसे सस्ती कीमतों पर खरीदने का अच्छा मौका है।

आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतें गिरावट पर रही। आज जानिए कितना सस्ता हुआ गोल्ड और सिल्वर, और आपके शहर में क्या है 10 ग्राम सोने का भाव

क्यों गिरा भाव?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार, वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेतों के कारण सोने और चांदी कीमतों में गिरावट देखने को मिली। बीच बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 350 रुपये गिरकर 59,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

क्या है आज सोने का भाव?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार, आज राजधानी दिल्ली में सोना 350 रुपये गिरकर 59,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबार में सोना 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आज सोना 1,911 डॉलर प्रति औंस पर था।

कितनी सस्ती हुई चांदी?

आज चांदी में 1,000 रुपये की गिरावट देखने को मिली। चांदी 73,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आज चांदी 22.94 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई।

आपके शहर में क्या है गोल्ड का रेट

गुड रिटर्न की वेबसाइट के मुताबिकः

दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,600 रुपये है।

नोएडा में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,600 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,450 रुपये है।

चैन्नई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,780 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,450 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,450 रुपये है।

केरल में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,450रुपये है।

पटना में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,500 रुपये है।

सूरत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,500 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,600 रुपये है।

ब्रिटिश पेट्रोलियम से बर्नार्ड लूनी ने दिया इस्तीफा, जानें वजह और किसे बनाया गया अंतरिम सीईओ

ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी बीपीके सीईओ बर्नार्ड लूनी ने इस्तीफा दे दिया है। बर्नार्ड लूनी ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि एक सहकर्मी के साथ उनके ऐतिहासिक संबंध पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थे जिसके कारण उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। जानिए उनकी जगह किसी बनाया गया है अंतरिम सीईओ।

नई दिल्ली। ब्रिटिश ऊर्जा दिग्गज बीपी के मुख्य कार्यकारी बर्नार्ड लूनीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बर्नार्ड लूनी ने यह स्वीकार करते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है कि वह सहकर्मियों के साथ ऐतिहासिक संबंधों के बारे में पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थे।

कंपनी ने बयान जारी कर दी सूचना

आपको बता दें कि बीपी (BP) ने एक बयान में कहा, बर्नार्ड लूनी ने कंपनी को सूचित किया है कि उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है।

कंपनी के इन्हें बनाया अंतरिम सीईओ

बर्नार्ड लूनी के इस्तीफे के बाद बीपी ने मरे औचिनक्लोस (Murray Auchincloss) को नया अंतरिम सीईओ बनाया है। 53 वर्षीय लूनी, चार साल से कम समय के पद पर रहे।

पिछले साल मई में मिली थी बीपी को शिकायत

बीपी ने कहा कि पिछले साल मई में उसके बोर्ड को कंपनी के सहयोगियों के साथ व्यक्तिगत संबंधों के संबंध में लूनी के आचरण से संबंधित एक अज्ञात स्रोत से आरोप प्राप्त हुए थे जिनकी समीक्षा की गई थी। समीक्षा के दौरान लूनी ने सीईओ बनने से पहले सहकर्मियों के साथ कुछ ऐतिहासिक संबंधों का खुलासा किया, बीपी ने यह भी कहा कि कंपनी की आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है।

प्रान्त संयोजिका अल्का गौड़ दीदी के नेतृत्व में मनाया विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस

आगामी 23 सितंबर को शौर्य जागरण यात्रा में आने हेतु महिलाओं को किया जागरूक

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। शहर की शारदा एवरग्रीन कोलोनी में प्रान्त संयोजिका अल्का गौड़ का प्रवास रहा। कोलोनी व आसपास की कालोनी की मातृशक्ति बहनो ने बड़े ही उत्साह पूर्वक इस प्रवास की बैठक में भाग लिया।जिसमें विभाग संयोजिका गायत्री सोनी ने सबका परिचय करवाया।वही जिला संयोजिका लक्ष्मी वर्मा ने आचार पद्धति करवाई और महानगर संयोजिका प्रेमलता शर्मा ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया।

प्रान्त संयोजिका अल्का दीदी ने बताया कि विश्व हिन्दु परिषद के षष्टी पूर्ति वर्ष में अधिक से अधिक बहने आगामी धर्म सभाओं मे भाग लेते हुए दिनांक 23 सितम्बर को शौर्य जागरण यात्रा में अधिक से अधिक बहने लाल चुनरी की साडी.पहन कर विराट धर्म सभा में भाग लेवें।

संयोजिका अल्का दीदी ने बताया कि आप सभी संगठित रहे और सत्संग के माध्यम से अधिक से अधिक बहनें आपस में जुड़कर रहते हुए अन्य महिलाओं में भी जागृति पैदा करे।कार्यक्रम में सत्संग प्रमुख कृष्णा त्रिपाठी ने गणेश वन्दना व सुशीला राजपूत सह सत्संग प्रमुख और तारा शर्मा,राजदुलारी शर्मा,गायत्री सोनी,मोनिया गुर्जर,लक्ष्मी विश्नोई,मोनू सोनी,कंचन साहू,मंजू गुर्जर आदि अनेक महीलाओं के साथ महानगर संयोजिका प्रेमलता शर्मा ने भजन कीर्तन किये,साथ ही विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक और सतसंग में जयमल राठौर नगर क्रमांक -7 की

शारदा कालोनी में आसपास की कॉलोनियों से आयी सभी महिलाओं का धन्यवाद कर आभार प्रकट किया और बाद में जयघोष करवाकर बैठक का समापन किया।

इसके पश्चात प्रांत संयोजिका अल्का गौड़ दीदी ने ग्रामीण प्रवास के अंतर्गत पुर प्रखण्ड मे प्रवास किया।जहाँ पुर में बहनों से मिलकर उनको भी सत्संग से जुड़ने,बालसंस्कार कैन्द्र चलाने के लिए मार्गदर्शन किया और शौर्य जागरण यात्रा में अधिक से अधिक संख्यां में धर्मसभा में भीलवाड़ा आने हेतु आमंत्रित किया।

युवा ब्रहशक्ति मेवाड़ भीलवाड़ा की महिलाओं ने मनाया नंदोत्सव

भीलवाड़ा। युवा ब्रहशक्ति मेवाड़ भीलवाड़ा की महिलाओं ने श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर लड्डूगोपाल को पालने में झुला झूलाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नंदोत्सव मनाया। युवा ब्रहशक्ति मेवाड़ के महिला संगठन की भीलवाड़ा जिलाध्यक्षा सुनीता व्यास ने बताया कि संगठन की महिलाओं ने युवा ब्रम्हशक्ति मेवाड़ की प्रदेशाध्यक्षा नीलम शर्मा के सानिध्य में भजन कीर्तन कर नंदोत्सव मनाया।

जिला उपाध्यक्षा पूजा शर्मा ने बताया कि इस नंदोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम महाराज की प्रतिमा को पुष्पमाला पहना दीप प्रज्जलित करके की गई। संगठन की सचिव संध्या शर्मा ने बताया कि इस नदोत्सव कार्यक्रम में पंडित देवराज व्यास द्वारा अनेकोनेक भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई जिस पर ब्रह्म शक्ति की महिलाओं ने भावविभोर होकर नाचते झूमते हुए लड्डूगोपाल जी को पालने में झूला झुलाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नंद उत्सव मनाया।

संगठन की रोजगार प्रकोष्ठ मंत्री रश्मि आचार्य ने बताया कि इस नंदोत्सव कार्यक्रम में दो महिलाओं को राधा कृष्ण का रूप धराकर झांकी बनाई गई बाद इसके बीच पांडाल के माखन मिश्री से भरी सजी धजी मटकी बांध लड्डूगोपाल के हाथों से उसका प्रसाद निकाल कर सर्वप्रथम राधामाधव के भोग लगाकर सभी महिलाओं में प्रसाद वितरण कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नंद महोत्सव मनाया गया।

इस दौरान युवा ब्रम्हशक्ति मेवाड़ भीलवाड़ा की वंदना जौशी, वंदना शर्मा, नीता चौबे, ज्योति भट्ट, सुमन त्रिवेदी, मंजू शर्मा, पूरण कला, सुनीता आचार्य, ऋतु शर्मा, सुशीला शर्मा, शारदा श्रोत्रिया, रेखा शर्मा, कौशल्या शर्मा, विमला पारीक सहित सभी महिलाओं ने रंगबिरंगी पोशाकों में मौजूद रहकर श्रीकृष्ण भगवान की राश लीलाओं का जमकर आनंद लिया।

विनायक विद्यापीठ भूणास का दबदबा बरकरार

अनूप कुमार शर्मा, भीलवाडा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धुवाला, करेड़ा के तत्वाधान में आयोजित 67वीं जिलास्तरीय हैंडबाल प्रतियोगिता 14 वर्षीय छात्र-छात्रा का आयोजन किया जिसमें फ़ाइनल मैच विनायक विद्यापीठ भूणास ने कवलियास को हराकर प्राप्त करते हुए प्रतियोगिता अपने नाम की। फ़ाइनल मैच में प्रिन्स खटीक और दुष्यंत बैरवा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया। विदित हैं कि गत वर्ष भी विनायक विद्यापीठ 14 वर्षीय हैंडबॉल छात्र वर्ग की विजेता रही थी साथ ही इस साल अपने उम्दा खेल प्रदर्शन से अपने ख़िताब को बचाने में सफलता अर्जित करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। इस उपलब्धि पर संस्थान निदेशक डॉ देवेंद्र कुमावत, संस्थान सचिव राज नायर, प्रधानाचार्य राधेश्याम पारिक, टीम कोच शीतल सिंह, टीम प्रभारी राजेश खटीक और संस्था कोऑर्डिनेटर डॉ यश कुमावत ने हर्ष व्यक्त करते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं की।

आम आदमी पार्टी ने शाहपुरा बनेडा मे केजरीवाल के गारन्टी कार्ड लोगों को बांटे

भीलवाडा। आम आदमी पार्टी का शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष पूरण खटीक के नेतृत्व में जोर शोर से शाहपुरा बनेडा मे जनसम्पर्क अभियान का आगाज किया जनसम्पर्क अभियान के तहत माताजी का खेडा व रेहड़ ग्राम प्रचायत मे जनसम्पर्क के माध्यम से लोगो को केजरीवाल की गारन्टीयो से अवगत कराया ओर एक मोका केजरीवाल को शाहपुरा बनेडा विधानसभा मे देने का आव्हान किया इस अवसर पर आम लोगों का भी जबरदस्त समर्थन मिला लोग बोल रहे कि हम केजरीवाल जी की गारन्टी ओर काम की राजनीति से प्रभावित हे ओर भाजपा ,कांग्रेस से दुखी हो गये हे इस बार शाहपुरा बनेडा विधानसभा मे आम आदमी पार्टी को मोका देगे इस जनसम्पर्क अभियान मे वरिष्ठ कार्यकर्ता ललित सिंह चौहान ,नूर मोहम्मद कायमखानी, गोविंद वैष्णव, सर्किल इंचार्ज सत्यनारायण रैगर,सर्किल इंचार्ज लक्ष्मण बंजारा,आदि कार्यकर्ता शामिल हुऐ है।

बिजेड़ी दल के बरिष्ठ नेता सौम्यरंजन पटनायक को उपाध्यक्ष पद से हटाया गया

मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर को लेकर आशंका जताई - सौम्यरंजन

परिवहन विशेष न्यूज

भुवनेश्वर। बिजेडी दल के वरिष्ठ नेता सौमरंजन पटनायक को उपाध्यक्ष पद से हटाया गया. बीजे सुप्रीम ने विधायक को पार्टी उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है. सौम्यरंजन पटनायक अखबार में संपादकीय लिखकर विवादों में थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार अखबारों में पार्टी विरोधी टिप्पणियाँ और संपादकीय लिखने को लेकर विवादों में है।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदर्शन पर सवाल उठाए. जिसे लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया था. एपिरिकी सौम्या के बयान की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया के सामने निंदा की. अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में आकर कहें। लेकिन फिर भी सौम्या चुप नहीं रहीं. वह लगातार पार्टी विरोधी टिप्पणियां कर रहे थे. आखिरकार मंगलवार को पार्टी सुप्रीमो ने खड़पाड़ा विधायक और बिजेड़ी दल उपाध्यक्ष सौम्यरंजन पटनायक के खिलाफ कार्रवाई की.

आखिरकार पार्टी विरोधी टिप्पणियों और लेखन के लिए बिजेड़ी दल सुप्रीमो नवीन पटनायक को उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है. बीजेडी पार्टी की ओर से एक नोटिस प्रकाशित किया गया है.

जाजपुर के विधायक और बीजेडे संगठन के संपादक प्रणब प्रकाश दास उर्फ बॉबी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर सौम्या पर टिप्पणी की है।

सौम्या को उपराष्ट्रपति पद से हटाए जाने पर बॉबी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कमेंट करते हुए लिखा, 'आभार प्रार्थना का सबसे अच्छा रूप है। जहां कृतज्ञता नहीं, वहां ईश्वर की ओर से कोई सहायता नहीं।' बॉबी की ऐसी टिप्पणियों को लेकर राज्य की राजनीति में खूब चर्चा शुरू हो गई है.

उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सौम्या की प्रतिक्रिया सौम्या ने मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर पर सवाल उठाया बर्खास्तगी पत्र पर मंत्री के हस्ताक्षर को लेकर मुझे संदेह है मैंने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 2 मिनट का समय मांगा आशंका है कि उन्हें बिना समय दिए बर्खास्त कर दिया गया अपना पद खोने पर सौम्या पटनायक ने रखी ये राय! मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ खोया है, मैं उस स्थिति में क्या कर रहा था? हमारी टीम में युवा क्या करते हैं? सौम्या पटनायक ने कहा कि हमारी पार्टी में पद सिर्फ सजावटी है।

और आम लोगो को नहीं होगी समस्या , युधकाल के आधार पर होगी समाधान - 5टी सचिब

भुवनेश्वर: अब नहीं होगी लोगों की परेशानी. समस्या का समाधान युद्धकाल के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ से लेकर 5टी सचिव जिला गश्ती तक प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। 5टी सचिव की जिला गश्ती के दौरान प्राप्त शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. सत्ता पक्ष ने कहा कि जनसेवा ही मूलमंत्र है और जनता की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर काम किया जाता है. दीर्घकालिक समस्याएं, युद्धकालीन समाधान। सीएमओ लोगों की शिकायतों को तूल दे रहे हैं। 5टी सचिव की जिला पुलिस को 53 हजार 953 शिकायतें मिली हैं. 30,000 से अधिक समस्याओं का समाधान किया गया। राज्य सरकार के फोकस में लोगों की शिकायतें. जनसेवा ही नवीन शासन का मूलमंत्र है. सरकार जनता की बात से चलेगी. जहां समस्या है, सरकार वहीं है. लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान किया जाएगा।

नशामुक्ति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कायर्शाला का आयोजन

भीलवाड़ा। संगम विश्वविद्यालय के सेन्टर फॉर एन्ट्रेप्रेन्योरशिप एवं स्किल डेवलपमेन्ट तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकारण मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति पर दो दिवसीय क्षमता निमार्ण कायर्क्रम का आयोजन सर प्रताप विधि महाविद्यालय, जोधपुर में किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह थे। उन्होंने भारत सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री के नशामुक्त भारत अभियान के बारे में विस्तृत चर्चा की तथा इसकी वतर्मान समय में प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। सत्र के अतिथि पद्मभूषण एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री नारायणसिंह माणकलाव ने नशे के विरुद्ध स्वयं द्वारा चलाए गए अभियान तथा उससे हुए अनुभवों को साझा किया। कायर्क्रम के विशिष्ट अतिथि नारकोट्क्सि कंट्रोल ब्यूरो (एन॰ सी॰ बी॰) के ज़ोनल डायरेक्टर श्री घनश्याम सोनी ने सरकार द्वारा मादक पदार्थ और इससे जुड़े अपराधों की रोकथाम के प्रयासों के बारे में बताया। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा के प्रो॰ आशीष्माथुर, सर प्रताप विधि महाविद्यालय के चेयरपसर्न श्री गिरीश माथुर, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के उप-निदेशक मनोज हतोज, आरंभ सेवा संस्थान, भीलवाड़ा के निदेशक विशाल खण्डेलवाल उपस्थित थे।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया आमजन को परिवर्तन यात्रा सभा में पधारने के लिये निमन्त्रण

महिलाओ ने बाटे पिले चावल

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। प्रदेश नेतृत्व द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा के कल भीलवाड़ा विधानसभा में आगमन को लेकर कार्यकर्ताओ में खासा जोश दिख रहा है यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूण हो चुकी है। विधानसभा प्रवक्ता पुनीत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज भाजपा सुभाष मण्डल अध्यक्ष मनीष पालीवाल के नेतृत्व में सूचना केन्द्र से बड़े मंदिर तक मण्डल पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आम को पीले चावल व पत्रक वितरण कर होने वाली सभा ने पधारने का निमंत्रण दिया।मंडल पदाधिकारी ने आम जन को यात्रा की जानकारी देते हुए कहा की आमजन को कांग्रेस के जंगल राज कुशासन,से छुटकारा दिलाने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है हम सब को मिल कर यात्रा को सफल बनाना है। तंवर ने बताया कि यात्रा शाम 6 बजे विधानसभा में प्रवेश करेगी आर.टी.ओ. रोड पुर रोड से वाहन रैली से कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जायेगा रैली के रूप में यात्रा रेलवे स्टेशन चौराहा पर पहुचेगी उस के बाद केन्द्र से पधारे मंत्रियों द्वारा जन सभा को संबोधित किया जायेगा। कार्यक्रम में महामंत्री आशिष बाल्दी,ललित व्यास,युवा मोर्चा अध्यक्ष अनुराग पारीक,उपाध्यक्ष अनिता आर्य,मंत्री चित्रा लोहानी,कृष्ण कुमार ,भैरु लाल पारीक सुजीत मेवाड़ा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी, तमिलनाडु के इन 2 स्टेशनों पर भी रुकेगी श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस

नई दिल्ली। दक्षिणी रेलवे (SR) के प्रवक्ता ने बताया कि तीर्थयात्रियों के साथ-साथ तमिलनाडु के रामनाथपुरम और कराईकुडी के लोगों की भी मांग थी कि इन स्थानों पर भी ट्रेन का स्टॉपेज हो। अधिकारी ने कहा कि दक्षिणी रेलवे ने ट्रायल के तौर पर इन दो स्टेशनों पर श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। रेल से सफर करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने बुधवार को सूचना दी कि साप्ताहिक ट्रेन श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस अब 20 सितंबर से तमिलनाडु के रामनाथपुरम और कराईकुड़ी स्टेशन पर भी रुकेगी। इस ट्रेन का संचालन तमिलनाडु के मंडपम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट के बीच होता है। श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस को 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। यह गाड़ी भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों को जोड़ती है। दक्षिणी रेलवे (SR) के प्रवक्ता ने बताया कि तीर्थयात्रियों के साथ-साथ तमिलनाडु के रामनाथपुरम और कराईकुड़ी के लोगों की भी मांग थी कि इन स्थानों पर भी ट्रेन का स्टॉपेज हो। अधिकारी ने कहा कि दक्षिणी रेलवे ने ट्रायल के तौर पर इन दो स्टेशनों पर श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। शेड्यूल के मुताबिक, एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु के रामेश्वरम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट के बीच चलनी चाहिए, लेकिन फरवरी से यह मंडपम से संचालित हो रही है, क्योंकि पम्बन पुल, जो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है, बंद कर दिया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि पुराना पंबन पुल बंद कर दिया गया है और एक नया पुल बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 2.078 किमी है।

लीबिया में तूफान-बाढ़ से 5 हजार लोगों की मौत:15 हजार लापता; 2 डैम टूटने से डेर्ना शहर तबाह, जगह-जगह लाशें मिल रहीं

परिवहन विशेष न्यूज

काहिरा/त्रिपोली। फुटेज डेर्ना शहर की है। यहां 2 डैम फूट गए। इसकी वजह से पूरे शहर में तबाही का मंजर है।

अफ्रीकी देश लीबिया में डेनियल तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा दी है। तूफान के बाद 10 हजार आबादी वाले डेर्ना शहर के पास दो डैम टूट गए। इससे पूरा शहर तबाह हो गया है।

देश में अब तक 5 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 हजार से ज्यादा लोग लापता हैं। सिर्फ 700 शव ऐसे हैं, जिनकी शिनाख्त हो सकी है।

रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे 123 सैनिकों के बारे में भी पता नहीं चल रहा है। यही वजह है कि अब फौज भी बेबस नजर आ रही है। देश में मौजूद चुनिंदा एयरपोर्ट्स इस लायक नहीं बचे हैं कि वहां कोई हैवी या कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। यही वजह है कि यहां मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो रही है।

हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि कई इलाकों में पानी में लाशें तैरती नजर आ रही हैं। कई घरों में शव सड़ चुके हैं।

सैटेलाइट इमेज डेर्ना शहर की है। बांध टूटने से पहले और बाद का मंजर देखा जा सकता है।

सैटेलाइट इमेज डेर्ना शहर की है। बांध टूटने से पहले और बाद का मंजर देखा जा सकता है।

पूरे डेर्ना शहर में बाढ़, लाशों की शिनाख्त नहीं हो पा रही

अल जजीरा के मुताबिक, पोर्ट सिटी डेर्ना के पास दो डैम थे, तूफान और बाढ़ से ये टूट गए। इनमें से एक डैम की हाइट 230 फीट थी। सबसे पहले यही डैम तबाह हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन डैम्स की 2002 से देखरेख नहीं हुई थी।

पूरा शहर बाढ़ का पानी आ गया है। 10 हजार आबादी वाले इस शहर में अब तक 700 लोगों की मौत हुई है। हालात इस कदर खराब हैं कि मरने वालों को दफनाने तक की जगह नहीं बची। लाशें सड़कों पर देखी जा सकती हैं।

डेर्ना शहर का 25% हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है।

आखिर इस तबाही की वजह क्या है

'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक- लीबिया में सरकार का होना या न होना बराबर है। पश्चिमी हिस्से के त्रिपोली में एक सरकार है। मुल्क के पूर्वी हिस्से में 80% तबाही हुई है। यहां दर्जनों कबीले हैं और हर कबीले का किसी न किसी हिस्से पर शासन है। जाहिर है, 2011 के बाद से ही लीबिया में कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार या कोई एक शासक नहीं है।

अमेरिका, स्पेन और तुर्किये साथ ही UN और रेडक्रॉस भी यहां मदद भेज रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये जरूरतमंदों तक पहुंचेगी? और अगर पहुंचेगी भी तो कैसे? क्योंकि, इन्फ्रास्ट्रक्चर नाम की तो चीज ही नहीं है और जो थी, वो भी बाढ़ में तबाह हो गई।

इसी डेनियल तूफान ने पिछले हफ्ते ग्रीस, तुर्किये और बल्गारिया में तबाही मचाई थी। वहां 12 लोगों की मौत हुई थी। यह तय था कि तूफान अब लीबिया की तरफ बढ़ रहा है। पांच दिन में यहां कोई कदम उठाए ही नहीं गए। सबसे ज्यादा तबाही दो डैम फूटने से हुई। अब तीसरा भी फटने की कगार पर है। दूसरी बात, लीबिया की ज्यादातर आबादी और शहर समुद्री किनारों पर हैं। इसलिए जब डेनियल तूफान यहां के कोस्टल इलाकों से टकराया तो बर्बादी ज्यादा हुई।

डेर्ना शहर के एक इलाके का एरियल व्यू। खराब सड़कों और कारों को देखा जा सकता है।

डेर्ना शहर के एक इलाके का एरियल व्यू। खराब सड़कों और कारों को देखा जा सकता है।

डेर्ना शहर में डैम का पानी इतनी तेजी से आया कि अपने साथ सबकुछ बहा ले गया।

डेर्ना शहर में डैम का पानी इतनी तेजी से आया कि अपने साथ सबकुछ बहा ले गया।

डेर्ना में तूफान के बाद सड़कों पर शवों को शिनाख्त के लिए रखा गया।

डेर्ना में तूफान के बाद सड़कों पर शवों को शिनाख्त के लिए रखा गया।

डेर्ना में बाढ़ के बाद सड़कें टूट चुकी हैं।

डेर्ना में तूफान और बाढ़ की वजह से कई घर और कारें मलबे में तब्दील हो गए।

डेर्ना में तूफान और बाढ़ की वजह से कई घर और कारें मलबे में तब्दील हो गए।

एरियल व्यू में तूफान की वजह से खराब हुई सड़क को देखा जा सकता है।

एरियल व्यू में तूफान की वजह से खराब हुई सड़क को देखा जा सकता है।

बाढ़ के बाद लोग आसपास के क्षेत्र से मलबा और सामान हटाते नजर आए।

बाढ़ के बाद लोग आसपास के क्षेत्र से मलबा और सामान हटाते नजर आए।

डेर्ना की गलियां पानी और कीचड़ से भर गई हैं।

डेर्ना की गलियां पानी और कीचड़ से भर गई हैं।

बेनगाजी शहर में जहां मेन रोड थी, अब वहां पानी और मलबा नजर आ रहा है।

बेनगाजी शहर में जहां मेन रोड थी, अब वहां पानी और मलबा नजर आ रहा है।

हेल्थ मिनिस्टर ने कहा- पानी में तैर रहीं हैं लाशें

हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, 'डेर्ना इलाके में हालात इस कदर खराब हैं कि कई जगहों पर तो पहुंचा भी नहीं जा सकता। यही वजह है कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि जमीनी हालात क्या होंगे। कई इलाकों में पानी में लाशें तैरती नजर आ रही हैं। कई घरों में शव सड़ चुके हैं और इनकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा है। मुझे लगता है कि डेर्ना शहर का 25% हिस्सा खत्म हो चुका है।

सरकार ने बताया कि आखिरी आंकड़ा आएगा तो शायद दुनिया हैरान रह जाए। इतने खराब हालात सिर्फ 1959 में हुए थे। दुनिया के कई देशों ने मदद की पेशकश की है, लेकिन अभी वो कैसे मदद कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। न एयरपोर्ट सलामत हैं और न सड़कें बची हैं।

अफ्रीकन देश लीबिया के बारे में जानिए...

लीबिया देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग में 17.6 लाख किमी स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी राजधानी त्रिपोली है। लीबिया की सीमा भूमध्यसागर, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाद, सूडान और मिस्र से मिलती हैं।

लीबिया की कुल आबादी 67.4 लाख है। 2021 के मुताबिक लीबिया की GDP 23 हजार करोड़ हैं। लीबिया का 95% रेवेन्यू पेट्रोलियम सेक्टर से आता हैं जो देश के GDP का 60% हैं। कम आबादी और पेट्रोलियम सेक्टर में ज्यादा मुनाफा होने की वजह से लीबिया की पर-कैपिटा इनकम 5 लाख के ऊपर हैं। इसी वजह से लीबिया प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 91 नंबर पर है।

सिर्फ नाम की सरकार

1911-12 के बीच इटली ने यहां आटमन एम्पायर को खत्म किया और लीबिया पर कब्जा कर लिया। 1920 के दौरान इटली के शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। बहरहाल, इस आंदोलन से आजादी मिलने में करीब 20 साल लगे। 1942 में इटली और उसके सहयोगी जर्मनी ने यह देश छोड़ने का फैसला किया। इसके बावजूद लीबिया में कबीलाई संघर्ष चलता रहा और 1951 में किंग इदरीस ने जाकर इसे बतौर मुल्क आजाद घोषित किया।

1956 के आसपास यहां ऑयल प्रोडक्शन पर फोकस किया जाना शुरू हुआ। 1969 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने किंग इदरीस का तख्तापलट दिया और खुद को शासक घोषित कर दिया।

2011 में देश के बड़े शहर बेनगाजी में गद्दाफी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए और फिर देश के कोने-कोने में फैल गए। इसी दौरान वो मारे भी गए। 2016 तक यह सिलसिला चला और इसी दौरान UN के दखल से यहां एक कमेटी बनी। इसे आप केयरटेकर सरकार भी कह सकते हैं।

2021 में इसी सरकार को बेहतर रूप दिया गया और अब्दुल हमीद इसके प्रधानमंत्री बने। 2023 में ऑयल रेवेन्यू शेयरिंग के लिए एक कमेटी बनी। हालांकि, इसका फायदा नहीं हुआ। यहां आज भी अलग-अलग कबीलों के बीच जंग जारी है। देश के बहुत कम हिस्से पर सरकार का नियंत्रण है।

'अल अरब' की एक रिपोर्ट के मुताबिक- लीबिया में 2011 के बाद से कोई सड़क तक नहीं बनी है। बेनगाजी शहर में फिलहाल, तुर्की ने 84 लोगों की मेडिकल टीम और कुछ दवाइयां भेजी हैं।

UN के मुताबिक- लीबिया के हालात पर नजर रखी जा रही है और कुछ इमरजेंसी प्लान भी बनाए गए हैं। हालांकि, वहां मदद पहुंचाने के लिए दूसरे देशों की मदद लेनी होगी। एक अफसर के मुताबिक- कुछ महीने पहले तुर्किये और सीरिया में भूकंप के बाद जो हालात बने थे, कुछ वही स्थिति लीबिया में भी है। सबसे पहले तो जमीनी हालात समझने होंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023